The Director, Mines Safety, Nagpur area has already conducted an enquiry into the accident and the detailed report is awaited. The Managing Director, Western Division of Coal Mines Authority Ltd., who visited the spot soon after the accident, has reported that at the time of the accident, the mine had full complement of supervisory personnel and it was being worked strictly according to the methods approved by the Mines Department.

A sum of Rs. 1,000 has already been given to the members of the families of the deceased persons as an *ad-hoc* grant and they have also been assured that jobs would be provided to the sons of the deceased persons. Injured persons will be placed on light jobs depending on the nature and extent of their injury.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : अध्यक्ष जी दुर्घटना 11 तारीख को हुई, आज 15 तारीख है। मैं जानना चाहता हूँ मंत्री महोदय को कब सूचना मिली? क्या सूचना आने में देर नहीं हुई? अगर हुई तो क्यों देर हुई?

श्री के० डी० मालवीय : हमको तो कल शाम को सूचना मिली और मैंने आज पेश कर दी।

श्री जगन्नाथ मिश्र (मधुबनी) : शिक्षक धरना पर हैं इसलिये अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय को वक्तव्य देने को कहें :

MR. SPEAKER: Please sit down. Such things can be referred to in the speech. The Budget is already under discussion. You can refer to it. Shri Mulk Raj Saini to continue his speech on the Budget.

SHRI P. G. MAVALANKAR (Ahmedabad): What is the reply of the Minister of Parliamentary Affairs to our points and request?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं।

MR. SPEAKER: I will ask him to tell it later on. Shri Mulk Raj Saini to continue his speech on the budget.

GENERAL BUDGET, 1974-75 GENERAL DISCUSSION—contd.

श्री मुल्की राज सैनी (देहरादून) : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि यह बजट ऐसे समय पर और परिस्थितियों में पेश किया गया है जो कि बहुत कठिन है और देश को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वास्ते मैं यह मानकर चलता हूं कि यह बजट एक बहुत अच्छा प्रयास है, जैसा कि सम्मानित सदस्यों ने भी कहा है। इसलिये मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि यह बजट समाजवादी नहीं है। यह बजट बहुत हद तक कल्याणकारी भी नहीं कहा जा सकता।

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

देश का बजट करोड़ों से अरबों में चला गया है, देश की योजनायें अरबों और खरबों की बन रही हैं। लेकिन जो देश के अन्दर अभाव की स्थिति है उसका समाधान इस बजट से नहीं दिखाई देता। मुद्रास्फीति देश में है और हर बजट में बढ़ती ही जा रही है। इस बार घाटे का बजट न बनाने का आश्वासन दिया गया था लेकिन फिर भी हमारे सामने एक घाटे का बजट है। हालांकि उस में घाटा 125 करोड़ रुपये का दिखाया गया है, लेकिन जैसी कि हाउस में शंकायें व्यक्त की गई हैं और सम्भावना इस प्रकार की दिखाई गयी है कि यह घाटा 125 करोड़ नहीं रहेगा बल्कि बढ़ते बढ़ते कहीं 1,000 करोड़ पर न पहुंच जाय। जब घाटा बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो टैक्स भी लगा दिये

[श्री मुल्की राज सैनी]

जाते हैं और उन सबका असर गरीब आदमी की जेब पर पड़ता है। महंगाई की मार से बड़ी मार उसी पर पड़ती है। 1960-61 में रुपये की कीमत के अनुपात में आज उसकी कीमत साढ़े 38 पैसे ही रह गई है। आर्थिक स्थिति हमारी बिगड़ती जा रही है। शहरों में रहने वाले, उद्योगों में काम करने वाले जो संगठित मजदूर हैं या सरकारी कर्मचारी हैं या ऐसे ही दूसरे समुदाय हैं वे आन्दोलन करके कुछ न कुछ अपनी तनख्वाह बढ़वा ही लेते हैं उनके अन्दर जागरूकता है, संगठन शक्ति है और कुछ न कुछ रिलीफ या सुविधा उसके बल पर वे प्राप्त कर ही लेते हैं। लेकिन गांवों में रहने वाली अस्सी फीसदी आबादी जिसके लिए कोई राशन की व्यवस्था नहीं है, वितरण की नहीं है वह किसी भी प्रकार से उचित दामों पर आवश्यक वस्तुएं नहीं ले सकती है और नतीजा यह होता है कि सारा भार उन पर ही पड़ जाता है। संगठित लोग कुछ न कुछ तरीके अख्तियार करके नाजायज भी करा लिया करते हैं।

देश में 23 करोड़ लोग गरीबी के स्तर से नीचे रहते हैं। उनके लिए कोई भी योजना नहीं है, उनकी समस्याओं का बजट में कोई जवाब नहीं है। उनका क्या होगा? चौथी योजना समाप्त हुई। पांचवी योजना के पहले साल का यह बजट है। लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान सामने नहीं आ रहा है। सरकार को इस पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिये। अगर कहीं वह जागरूक हो गई, संगठित हो गई तो आज जिस तरीके से गड़बड़ी देश में चल रही है, उस में भी वही तरीके काम में लाने शुरू कर दिए तो देश को सम्भाल पाना मुश्किल हो जाएगा। उनकी मांग पेट की मांग है। जिस तरह से असन्तोष उस में व्याप्त होता जा रहा है अगर इसी तरह से वह होता चला गया तो हमारी सारी स्थिति ही बिगड़ सकती है।

बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है पढ़े लिखों और बेपढ़े लिखों, दोनों की। पता नहीं चलता इसके लिए कौन सी योजना आप बनाने जा रहे हैं। कब तक गरीब हौसला रखते? कब तक अनुशासन में रहते? किस तरह से वे लोग अपना पेट भरें, इसका कोई तरीका तो होना चाहिये। आप खास तौर पर इस पर विचार करें।

कुछ दिशा इस बार जरूर बदली है और उसके लक्षण जरूर नजर आते हैं लेकिन फिर भी इस बजट को हम समाजवादी या कल्याणकारी बजट नहीं कह सकते हैं। जब तक हम देश की स्थिति को सामने नहीं रखेंगे तब तक हम जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति की ओर नहीं बढ़ सकेंगे। आज स्थिति यह है कि अमीरों और गरीबों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। इस खाई को आपको पाटना होगा। गरीब पिस रहा है और जो अमीर है वह और ज्यादा अमीर होता जा रहा है। यह जो खाई बढ़ रही है इसको आप पाटें। बेरोजगारी बढ़ रही है घट नहीं रही है। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और जीवन की आवश्यकतायें पूरी नहीं हो रही हैं। 23 करोड़ व्यक्ति गरीबी के स्तर से नीचे रह रहे हैं। समाजवाद इस चीज की इजाजत नहीं देता। उस में इसके उलट होता है। छोटे और बड़े के बीच आय का अन्तर मिटा करता है और बराबरी की तरफ बढ़ा जाता है। उस में बेरोजगारी नहीं होती है। लेकिन हमारा जो नक्शा है उस में उस तरफ बढ़ने की बात नहीं है।

मुद्रास्फीति को रोकने की कोई राष्ट्रीय नीति आपने नहीं अपनाई है, बेरोजगारी मिटाने को कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई है, बढ़ती हुई कीमतों को रोकने की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई है,

शिक्षा प्रचार की भी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं अपनाई गई है। इसकी राष्ट्रीय नीतियां बननी चाहिये। जब तक ऐसा नहीं होगा कार्यक्रम नहीं बनेगा और कार्यक्रम नहीं बनेगा तो उस के अनुसार बजट नहीं बन सकता है।

बजट में कुछ सुविधायें दी गई हैं, छोटे आदमी को भी कुछ राहत पहुंचाने की बात है। साथ साथ बड़े आदमियों को भी राहत दी गई है। आयकर की सीमा को पांच हजार से बढ़ा कर छ: हजार कर दिया गया है। बड़े आदमियों पर जहां 97 परसेंट कर लगता था उसको घटा कर 77 परसेंट कर दिया गया है। ऐसा करने के पीछे जो मंशा है वह यह बताया गया है कि जो निहित स्वार्थ वाले लोग हैं वे अपने पैसे को कुछ विकास की तरफ लगाएंगे। विचार तो यह अच्छा प्रतीत होता है लेकिन इसका क्या परिणाम निकलता है यह भविष्य ही बताएगा।

बजट में इंडायरेक्ट टैक्सों का ही ज्यादा सहारा लिया गया है। इन से 186 करोड़ अर्जित करने का आपका विचार है। सीधे टैक्सों का असर धनी वर्ग और ऊंचे स्तर वालों पर पड़ता है। उन से केवल 14.5 करोड़ लेने की बात ही कही गई है। मैं समझता हूं कि सीधे टैक्सों पर आपको ज्यादा जोर देना चाहिये था अगर हम कल्याणकारी और समाजवादी बजट बनाना चाहते हैं क्योंकि बड़े व्यक्तियों की आमदनी में से सरकार कुछ हिस्सा अपने खजाने में ले भी ले तो वह कल्याणकारी और समाजवादी नीतियां अपना कर छोटे लोगों को ऊपर लाने के लिए कार्य कर सकती है।

आपने पोस्ट कार्ड की कीमत बढ़ाई है जिस को गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। पोस्ट कार्ड, टुथ पेस्ट, साबुन आदि ऐसी चीजें हैं जो आज निम्न वर्ग तथा मध्यम वर्ग तथा छोटे आदमी अधिक इस्तेमाल में लाते हैं। जब भी आप टैक्स लगाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जीवन की आवश्यक वस्तुएं जिन को गरीब आदमी, निम्न श्रेणी का आदमी, मध्यम श्रेणी का आदमी इस्तेमाल करता है उन पर टैक्स न लगें। हमेशा ही आपको लग्जरी गुड्स, ऐश और आराम की चीजों पर टैक्स लगाना चाहिये। इन चीजों को निहित स्वार्थ वाले, बड़ी आमदनियों वाले इस्तेमाल करते हैं। अगर उनकी जेबों पर इसका असर पड़ता है, उन पर बोझा पड़ता है तो किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है। उस पैसे से आप गरीबों के लिए कल्याणकारी काम कर सकेंगे।

उपज बढ़ाने के लिए कुछ प्रभावशाली कदम उठाने का विचार है। कोयले पर अभी काफी बहस हो चुकी है। उसकी उपज बढ़ाने के लिए 97 करोड़ रखा गया है। पहले 24 करोड़ था। पावर जैनरेशन के लिए 121 करोड़ रखा गया है। राज्यों का 790 करोड़ अलग है। स्टील की पैदावार के लिए 162 करोड़ रखा गया है। नान फैरस मैटल्ज के लिए 75 करोड़। खानों के लिए 163 करोड़ रखा गया है। कृषि उपज के लिए 246 करोड़ रुपया रखा गया है, और माननीय वित्त मन्त्री ने यह विश्वास दिलाया है कि कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए फंड्ज की कमी महसूस नहीं होने दी जायेगी। माननीय मन्त्री का यह आश्वासन स्वागत-योग्य है।

बजट से यह भी पता चलता है कि इस बार प्राइवेट सेक्टर में पैदावार या तो कम हुई है और या उतनी ही रह गई है, जब कि पब्लिक सैक्टर ने अपने लक्ष्य पर पहुंचने की कोशिश की है और इस साल लाभ भी अर्जित किया है। उद्योगों का उत्पादन बढ़ाने के बारे में सरकार को खास तौर से सतर्क रहना होगा, क्योंकि देश में आज इस तरह की साजिश चल रही

[श्री मुल्की राज सैनी]

है कि किसी तरह पैदावार कम हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अस्त-व्यस्त हो जाये, और देश में ऐसा असन्तोष फैल जाये कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के लिए संकट पैदा हो जाये।

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक बहुत गलत परम्परा प्रचलित की जा रही है। रेलवे विभाग में, जो देश का सब से बड़ा उद्योग है, घाटा होता है, और उस घाटे की पूर्ति सामान्य बजट से धनराशि ले कर की जाती है। पिछले साल रेलवे विभाग को 181 करोड़ रुपया दिया गया था और इस बार 342 करोड़ रुपया दिया गया है। यह प्रवृत्ति देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। अगर इतना बड़ा उद्योग प्राइवेट हैंडस में होता, तो मैं समझता हूं कि इतना घाटा कभी नहीं हो सकता था। इस प्रश्न पर राष्ट्रीय स्तर पर सोचना चाहिए और इस परम्परा को खत्म करना चाहिए।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, वह निःशुल्क, अनिवार्य और सब के लिए समान होनी चाहिए। आज हमारे देश में एक वर्ग वह है, जो शिक्षा प्राप्त करना तो दूर रहा, शिक्षा का स्वप्न भी नहीं ले सकता है, जब कि दूसरे वर्ग के लड़के-लड़कियां फैन्सी स्कूलों में पढ़ते हैं, इंगलैण्ड और अमरीका जा कर शिक्षा प्राप्त करते हैं। एक तरफ पैसे के क्षेत्र में इतनी बड़ी खाई है और दूसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में इतनी बड़ी खाई है। जो लोग शिक्षा में पिछड़े हुए हैं वे हमेशा पिछड़े रहेंगे। उन के बच्चों को नौकरी पाने का मौका कभी नहीं मिलेगा जब कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हुए लोगों को नौकरी मिलेगी, उन की स्त्री, उन के लड़के, लड़के की बहू और लड़की को नौकरी मिलेगी। एक घर में तो रोज-गार ही रोजगार होगा और दूसरे घर में बेरोज-गारी होगी?

हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा सवाल है। गांवों का विकास एक ऐसा कार्य है जिस से बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है। ग्राम विकास के नाम पर बहुत कुछ होता है, लेकिन गांवों की वास्तविक प्रगति नहीं हो पाती है। मैं इस सम्बन्ध में छोटी सी योजना पेश करना चाहता हूं। शहरों के चारों तरफ गांवों को सड़कों से मिला दिया जाये और गांवों में पानी और बिजली की व्यवस्था की जाये। सड़कों से मिलते ही शहरों में नौकरी करने वाली गांवों की जनता शहर में मकान नहीं लेगी, बल्कि अपने घर से बस, टैक्सी, साइकिल या तांगे से वहां पहुंच जायेगी। इस प्रकार उन लोगों को शहर और गांवों में दो घर बसाने नहीं पड़ेंगे और उन की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिणाम यह होगा कि पढ़ा-लिखा जागरूक आदमी गांव में बसेगा और अपने गांव का उत्थान करेगा। गांव में सभी सुविधायें उपलब्ध होंगी, वहीं स्कूल खुलेंगे, छोटे उद्योग लगेंगे और छोटे-छोटे बाजार डेवेलप होंगे। गांवों के विकास के साथ-साथ ओवर-सियर और इंजीनियर आदि प्रशिक्षित लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सरकार को ऐसी योजनाओं को हाथ में लेना चाहिए, जिन में अनुदान दे कर और प्रोत्साहन दे कर काम चल सकता हो। गांवों का विकास और वहां के हाउसिंग की बाइटल प्राबलम का समाधान इसी प्रकार हो सकता है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट को वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत की गई कसौटी पर ही कसना चाहता हूं। वित्त मन्त्री ने अपने बजट-भाषण के प्रारम्भ में यह कसौटी सामने रखी है—उन के शब्दों में :

"प्रत्येक केन्द्रीय बजट का मुख्य लक्ष्य यह होता है कि द्रुत विकास, स्थायित्व, अधिक से अधिक सामाजिक न्याय और आत्म-निर्भरता की

जाने की आवश्यकताओं के बीच उचित समन्वय लाया जाये।'

अगर हम विकास की कसौटी पर इस बजट को कस कर देखें और अब तक जो बजट पेश किये गये हैं उन की पृष्ठभूमि मे इस को देखें तो खेद के साथ कहना पड़ेगा कि हमारा विकास न केवल बन्द हो गया है बल्कि कुछ क्षेत्रों मे हम पीछे हट भी रहे हैं। राष्ट्रीय विकास की दर गिरी है। रुपये के मूल्य मे कमी आई है। जब प्रोफेसर दांडेकर और प्रोफेसर रथ ने 60वें दशक में गरीबी के स्तर के नीचे के लोगों की गणना की थी, तो उस गणना के अनुसार भारत के 40 फीसदी लोग गरीबी के स्तर के नीचे अर्थात् कंगाली का जीवन बिता रहे थे। अब यह संख्या सरकारी तौर पर बढ़ कर 44 फीसदी हो गई है। प्रति-व्यक्ति आय मे कमी हुई है। यहां तक कि जरूरत की चीजों की प्रति-व्यक्ति खपत भी घटी है। सुनने मे यह बात विचित्र मालूम होती है लेकिन यह बात सच है कि अनाज, खाद्य, तेल और मोटे कपड़े की प्रति-व्यक्ति खपत हमारे देश मे घटी है।

प्रोफेसर शिनाय के अनुसार दाल आम आदमी के लिए प्रोटीन का सर्वोत्तम साधन उपलब्ध करती है। 1961 में दाल की प्रति-व्यक्ति प्रति-दिन की खपत 2.43 औंस थी लेकिन 1972 में इस में 32 फीसदी की कमी हो गई है। प्रोफेसर शिनाय के विचारों से श्री भगत को मतभेद हो सकता है।

श्री बी० आर० भगत (शाहाबाद) पूरा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन आंकड़ों से मतभेद नहीं हो सकता है। आंकड़े या तो सच होंगे या गलत होंगे। आंकड़ों से भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उन की आलोचना अवश्य चुनौती दे सकते हैं, लेकिन तथ्यों से झगड़ा करने से काम नहीं चलेगा। स्पष्ट है कि विकास की कसौटी पर हमारे बजट खरे नहीं उतर रहे हैं।

वित्त मंत्री ने दूसरी कसौटी बताई है अधिक से अधिक सामाजिक न्याय। लेकिन अधिक से अधिक सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा, जब आमदनी और खर्च में विषमता बढ़ रही है? सचमुच में यह ताज्जुब की बात है कि देश में खेतिहर मजदूरों की संख्या की वृद्धि हो रही है। उत्तर प्रदेश के आंकड़े मेरे पास हैं वहां 1951 में खेतिहर मजदूरों की संख्या 22 लाख थी, जब कि 1971 में यह संख्या बढ़ कर 52 लाख हो गई। इस का अर्थ यह है कि जो मार्जिनल फ़ार्मर हैं, किनारे के किसान हैं, वे खेती के द्वारा जीवन-यापन सम्भव नहीं पा रहे हैं, वे खेती छोड़ कर मजदूरी में लग रहे हैं।

हम भूमि सुधारों की चर्चा कर रहे हैं, भूमि-हीनों के लिये अतिरिक्त भूमि के वितरण की योजनायें कर रहे हैं। फिर भी खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ना इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों की संख्या मे वृद्धि हो रही है। शहरी क्षेत्र में भी, जिन्हें प्रोफ़ेसर दांडेकर अरबन पूअर कहते हैं, बढ़ रहे हैं। अगर इस संख्या में वृद्धि होती है तो अधिक से अधिक सामाजिक न्याय देने का वित्त मंत्री का उद्देश्य कैसे पूरा हो सकता है?

रोजगार के दफ्तरों में दर्ज बेकारों के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, वे इस प्रकार हैं :

1971 में 51 लाख, 1972 में 69 लाख, 1973 में 81 लाख और 1974 में 96 लाख सभी जानते है कि बेकारों की वास्तविक संख्या इस से कहीं अधिक है।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : पापुलेशन बहुत बढ़ रही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या पैदा होते ही लड़का बेकार हो जाता है?

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

वित्त मंत्री ने तीसरी कसौटी बतायी है स्वावलम्बन। स्वावलम्बन हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है। हम स्वावलम्बन की चर्चा करते हैं। जब विश्व बैंक की रिपोर्ट आती है और हमारा पराबलम्बन उजागर करती है तो हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान आहत हो जाता है। लेकिन वित्त मंत्री के बजट में मुझे यह देख कर ताज्जुब हुआ कि पिछले साल जितनी विदेशी सहायता की हम ने कामना की थी और अनुमान किया था, इस वर्ष उन के बजट भाषण में उस से अधिक विदेशी सहायता का अनुमान किया गया है। उस के अनुसार 144 करोड़ रुपये की हम अधिक विदेशी सहायता की कामना कर रहे हैं। लेकिन जानकार लोगों का कहना है कि यह आंकड़े भी ठीक नहीं हैं। इन आंकड़ों में हम सोवियत रूस से गेहूं के रूप में जो ऋण प्राप्त कर रहे हैं और तेल उत्पादन करने वाले देशों से जो सहायता ले रहे हैं उस का समावेश नहीं किया गया है। अगर वह सहायता जोड़ ली जाय तो विदेशी सहायता 12 सौ करोड़ तक जायगी, इस बात की संभावना है। अब यदि विदेशी सहायता की मात्रा बढ़ती है तो स्वावलम्बन का उद्देश्य कैसे पूरा होता है?

मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो इस बात के लिए संतोष कर लें कि पी एल 480 के बारे में समझौता हो गया लेकिन इस बात का उल्लेख न करें कि पी एल 480 का एक दूसरा रूप सोवियत रूस के साथ हमारे आर्थिक संबंधों का जो विकास हो रहा है उस शक्ल में हमारे सामने आ रहा है। रूस से हम गेहूं ले रहे हैं तो वह किस भाव पर हमें मिलेगा? हम सोवियत रूस से तेल ले रहे हैं उस का भाव क्या है? हम फर्टिलाइजर प्राप्त कर रहे हैं उस का मूल्य क्या है? हम इस्पात ले रहे हैं उसकी कीमत क्या है? हम न्यूजप्रिन्ट भी सोवियत रूस से प्राप्त करना चाहते हैं। अन्तरराष्ट्रीय भावों की तुलना में सोवियत रूस के भाव क्या हैं इन के बारे में सदन को और देश को विश्वास में लेने की आवश्यकता है।

आत्म-निर्भरता का यह रूप नहीं हो सकता कि अमेरिका के संदर्भ में अपनी आत्म-निर्भरता घटा दें और सोवियत रूस के संबंध में अपनी निर्भरता बढ़ा दें। निर्भरता खतरनाक है वह चाहे इस महादेश पर हो या उस महादेश पर हो। यह धारणा गलत है कि विदेशी सहायता बिना शर्तों के मिलती है। शर्तें कभी दिखाई देती हैं कभी दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन जब संकट की घड़ी आती है तो शर्तें उजागर हो जाती हैं और हमारे राष्ट्रीय विकल्प को बन्द कर देती है। उस पर बढ़ती हुई निर्भरता कम से कम हमारी आत्म-निर्भरता की सूचक नहीं हो सकती है।

श्री सतपाल कपूर (पटियाला) : एक डेलीगेशन लेकर जाइए आप।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : डेलीगेशन में तो आप को जाने का मौका मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस कामना के बावजूद कि मूल्य स्थिर होंगे, कर प्रस्तावों से कुल मिला कर मूल्यों में वृद्धि होगी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। यह ठीक है कि वित्त मंत्री अपने को दो पाटों के बीच में पिसता हुआ पाते हैं। एक ओर तो यथार्थवाद है जो उन्हें व्यावहारिक नीतियों का अवलम्बन के लिए प्रेरित करता है, जो उन्हें इस बात के लिए तैयार करता है कि वह पूंजी निवेश को प्रोत्साहन दें जिससे उत्पादन बढ़े, लोग पूंजी बचाएं, अधिक से अधिक उद्योगों में लगाएं और विकास के लिए अनुकूल वातावरण बने लेकिन दूसरी ओर प्रगतिवाद, रैडिकलिज्म।

एक माननीय सदस्य : समाजवाद।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : समाजवाद जरा पुराना पड़ गया है। आजकल रैडिकलिज्म का जमाना है। यह उन्हें यथार्थवादी बनने से रोकता है। अब इस बजट की जो प्रतिक्रिया हुई है वह वित्त मंत्री के धर्म संकट को स्पष्ट कर देती है। वित्त मंत्री ने कुछ ऐसे कदम

बनाएं हैं जिन से उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। होगी या नहीं यह मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता। उन्होंने साढ़े सत्तानबे प्रतिशत से 77 प्रतिशत आयकर घटाया है। उद्योग के लिए जो डेवलपमेंट रिबेट 1974 में खत्म होने वाली थी उस की अवधि बढ़ाई है। ये कदम स्टाक एक्सचेंज के स्वागत में रूप में लिए गए हैं। कल तो हमारे मित्र श्री पीलू मोदी ने भी इनकी तारीफ कर दी। मगर वित्त मंत्री की मुश्किल यह है कि श्री पीलू मोदी जितनी उन की तारीफ करेंगे हमारे मित्र श्री इन्द्र जीत गुप्त उतनी ही उन की निन्दा करेंगे। ऐसी स्थिति में वे करें क्या ? मेरा निवेदन है कि समाजवाद, पूंजीवाद यह शब्दावली पुरानी पड़ गई है घिस पिट गई है ....

श्री पीलू मोदी (गोधरा) . अखंड भारत लाओ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मगर अखंड भारत लाने के लिये श्री पीलू मोदी को अपने मित्र जुल्फी को तैयार करना पड़ेगा।

श्री पीलू मोदी . वही अब आप को बचा सकता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप को नहीं बचा पाया तो हम को क्या बचाएगा ?

उपाध्यक्ष महोदय, जिन देशों में हमारी कल्पना के अनुसार पूंजीवादी सरकारें चलती हैं वहां भी सरकारों का स्वरूप अब कल्याणकारी हो गया है। आम नागरिक की बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति हर एक शासन का धर्म है। किसी भी विचारधारा से शासन सत्ता बंधी हो, उसे नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के दायित्व का निर्वाह करना होगा। जो शासन ऐसा नहीं करेगा वह टिक नहीं सकेगा चाहे कितनी भी ऊंची उद्घोषणाएं करे।

दूसरी ओर स्कैंडिनेविया के जिन देशों में पिछले बीस, पच्चीस सालों से समाजवादी सरकारें चल रही थी वहां की जनता ने परिवर्तन के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है। चुनाव में समाजवादी सरकारें परास्त हो रही हैं। पालने से लेकर शिक्षा तक नागरिक की चिन्ता करने वाली राज्य व्यवस्था लोगों को पर मुखापेक्षी बनाती है, उन्हें आलस्य से ग्रस्त करती है, उन के पराक्रम पर पानी फेरती है उनके पुरुषार्थ को कुंठित करती है। स्पष्ट है कि हमें बीच के रास्ते का अवलम्बन करना होगा। यह सरकार बीच के रास्ते का अवलम्बन करने का प्रयत्न भी करती रही है। लेकिन इस में राजनीति बाधक है।

वर्तमान सरकार की कठिनाई यह है कि वह आर्थिक प्रश्नों का राजनैतिक हल निकालना चाहती है। ये राजनैतिक हल थोड़े दिनों के लिये हमारे काम के हो सकते हैं मगर अन्ततोगत्वा ये देश की अर्थ-व्यवस्था को सबल और स्वस्थ नहीं बना सकते।

मुझे यह जान कर बड़ा आश्चर्य हुआ है कि जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीय करण हमने प्रगतिवाद की बड़ी दुदुंभि बजा कर किया था वे राष्ट्रीयकृत बैंक मुनाफे की दृष्टि से, प्राफिटेबिलिटी की दृष्टि से जो कसौटी निर्धारित की गई थी उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। हम ने बैंक लिए। बदले में मुआवजा दिया। यह आशा की जाती थी कि बैंक कम से कम 5.5 प्रतिशत का मुनाफा कर के दिखाएंगे जिस हिसाब से में उन के बदले में क्षतिपूर्ति देनी पड़ी थी।

लेकिन इन 14 बैंको का इतिहास क्या है, उन की उपलब्धियां क्या हैं ? 1971 में यह प्राफिटेबिलिटी 5.1 परसैन्ट थी, लेकिन 1972 में 4.9 परसैन्ट और 1973 में 3.8 परसैन्ट रह गई। मुझे स्मरण है कि एक चुनाव सभा में रक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम ने मुरादाबाद में स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण विफल हो

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

गया है क्योंकि इस के द्वारा जिन वर्गों को लाभ मिलना चाहिये था उन को लाभ नहीं मिला। कुछ बैंक तो गहरे संकट में फंस रहे हैं। इलाहाबाद बैंक जिस का मुनाफ़ा 1971 में 4.2 परसैन्ट था, 1972 में 2.2 परसैन्ट रह गया। बैंक आफ महाराष्ट्र का मुनाफा 1971 में 7 परसैन्ट था, 1972 में 0 परसैन्ट रह गया। सैन्ट्रल बैंक के 1971 और 1972 के मुनाफे में कोई अन्तर नहीं है, 1.9 परसैन्ट है, लेकिन हमने मुनाफे की जो कसौटी निर्धारित की है, उस के आधार पर बहुत कम है। इण्डियन ओवर सीज बैंक का मुनाफ़ा 1971 में 3.2 परसैन्ट था, लेकिन 1972 में 0.5 परसैन्ट रह गया। यूनियन बैंक आफ इण्डिया का मुनाफ़ा भी घटा है।

14 hrs.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं—वित्त मंत्री इन मुद्दों का जवाब देते हुए य कह सकते हैं कि बैंको का रिजर्व है और अपना रिजर्व दिखा कर बैंक यह दावा कर सकते हैं कि वे किसी आर्थिक संकट में घिरे हुए नहीं हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के आज तक के रंग-ढंग और उनकी उपलब्धियों व अनुपलब्धियों के बारे में गहराई से विचार होना चाहिये। मुझे कई ऐसे उदाहरण मालूम हैं जिन में राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये लक्ष्य निर्धारित कर दिये जाते हैं—रुपया जमा करने के फिर कर्मचारियों और अधिकारियों को मजबूर किया जाता है—उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये और वे लक्ष्यों को किस तरह से पूरा करते हैं—एक उदाहरण मेरे सामने है। अगर वित्त मंत्री चाहेंगे तो उस का ब्यौरा भी दे सकता हूं एक व्यक्ति से कहा गया कि बैंक में रुपया जमा करा दो। उस से 20 हजार रुपया जमा करा लिया गया, लेकिन फिक्स्ड डिपाजिट में दो लाख रुपया कागज में लिख दिया गया। 2 लाख रुपया फिक्स्ड डिपाजिट के बदले। उसे एक लाख 80 हजार का कर्जा दे दिया गया 20 हजार रुपया जो उस ने जमा किया था, वह काला धन था, लेकिन 20 हजार के बदले एक लाख 80 हजार का कर्जा पा लिया...

श्री सतपाल कपूर। वह कौन सा बैंक है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह 1 लाख 80 हजार भी कालधन का है – इस तरह की कई घटनायें हो रही हैं।

श्री सतपाल कपूर : ब्यौरे की बात नहीं, नाम बोलिये। कहानी न सुनाइये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप को कहानी लगती है—यही तो देश का दुर्भाग्य है।

श्री सतपाल कपूर : आप कहानी सुना कर चले जाते हैं—यह भी दुर्भाग्य है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी। हम कहीं नहीं जायेंगे यहीं आप का सिर खायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज बैंक व्यवस्था क्या होगी ? क्या कालेधन को सफेद धन बनाने के साधन रूप में बैंकों को प्रयुक्त होने की इजाजत दी जायगी ? क्या हम राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्षमता घटने देंगे, क्या हम आंकड़ों के रूप में लक्ष्यों को निर्धारित कर के इस तरह की अनियमितताओं को प्रोत्साहित होने देंगे? यदि वित्त मंत्री इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट मंगा सकते हैं, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिसाब की जांच पड़ताल करते हैं और यदि आवश्यकता होगी तो मैं उन को इस के बारे में और अधिक जानकारी भी दे सकता हूं।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जानकारी तो मैं चाहूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं किसी संकुचित दृष्टिकोण से यह बात नहीं कह रहा हूं। आज कोई भी दल ऐसा नहीं कहता कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को पुनः निजी हाथों में सौंप देना चाहिये। इस बात से भी इन्कार नहीं

किया जा सकता कि कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने जहां पहले कर्जा नहीं मिलता था, कर्जा देना प्रारम्भ किया है, खेती के लिये, छोटे उद्योग धन्धों के लिये, जो आवश्यकता हम महसूस करते थे, उस की दिशा में राष्ट्रीयकृत बैंक बढ़े हैं, लेकिन जो अनियमितताएँ आज कायम हैं, वे हमारी दृष्टि से ओझल नहीं होनी चाहिए और हमें उन को ठीक करने का निरन्तर प्रयास करते रहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, बैंकों से सरकार द्वारा अन्धाधुंध कर्जा लेने की जो प्रवृति बन रही है, उस को भी बन्द करने की आवश्यकता है। सरकार ही नहीं, बड़े बड़े उद्योग और व्यापारी भी बैंकों से कर्जा प्राप्त करने आ रहे हैं आगे आ कर ऋणों की यह प्रक्रिया, उदार प्रक्रिया मुद्रास्फिति को बढ़ावा देती है। जिस मात्रा में धनराशि जमा होती है उस से अधिक कर्ज दिए जाते हैं। कुछ अर्थ शास्त्रियों ने जो गणना की है, उनकी रिपोर्ट के एक वाक्य को उद्धृत करना चाहता हूँ —

"During the end of 1969 and of third week of January 1974, bank credit has increased by 87 per cent."

उसी रिपोर्ट का एक दूसरा हिस्सा है —

"Whereas bank credit financed six per cent of government expenditure in 1968-69, this proportion has risen to 13 per cent in 1972-73."

आर्थिक समीक्षा में बड़े स्पष्ट रूप में यह स्वीकार किया गया है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था मुद्रा स्फिति से ग्रस्त है। जितना उत्पादन बढ़ना चाहिए—माल और सेवाओं के रूप में, उतना उत्पादन नहीं बढ़ा। मुद्रा की आपूर्ति बढ़ी लेकिन मुद्रा की आपूर्ति जो कर्ज के रूप में जाती उस की भी गणना उस में शामिल की जानी चाहिए।

उदाहरण के लिए पिछले साल यह कहा गया लेकिन घाटा 87 करोड़ रुपये का होगा, लेकिन यह घाटा बाद में जा कर 650 करोड़ का निकला। मेरा निवेदन है कि यह रकम 650 करोड़ से भी ज्यादा है, यह रकम 1643 करोड़ रुपये है, क्यों कि इसमें नेट-क्रेडिट हम को जोड़ना होगा। इसमें यह नहीं जोड़ा गया है, घाटा कम करके दिखाया गया।

इस बार के बजट में भी कहा गया है कि 125 करोड़ रुपये का घाटा होगा, मैं नहीं समझता कि किस उम्मीद में इस को कम कहा गया है, यह तो बढ़ने वाला है। इस लिए बढ़ने वाला है कि अनाज के लिए किसानों को हमें ज्यादा मूल्य देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन अधिक दाम देने की बात से सहमत हो गया है। राज्य सरकारें उस से भी दो कदम आगे चली गयी है। वित्त मंत्री के स्वयं अपने राज्य महाराष्ट्र में गेहू की कीमत 105 रुपये क्विंटल करने का सुझाव दिया है; मुख्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। हम आशा करते हैं कि उसमें एक सामान्य मूल्य नीति का निर्धारण किया जाएगा।

अब इस तथ्य से आंखे नहीं मूंदी जा सकती कि भारत का कृषक कम मूल्य स्वीकार नहीं करेगा। उसे कोई भड़काये- इस की आवश्यकता नहीं है? मुझे दुख है कि मेरे दल पर आरोप लगाया गया है कि हम ने किसानों को भड़का दिया, इस लिए किसान अधिक मुल्य मांग रहे हैं। हम अपने किसानों को इतना नासमझ न समझें। जब वह देखता है कि उस से कम दाम पर माल खरीदा जा रहा है और बाजार में अधिक दाम पर वही माल मिल रहा है तो उसे कम दाम पर बेचने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।

बड़ किसानों पर लेवी से सिद्धान्ततः किसी का विरोध नहीं हो सकता, लेकिन लेवी का अनुभव यह है कि बड़े किसान अफसरों के साथ तालमेल स्थापित कर के, सांठ गांठ कायम कर के लेवी से बच जाते हैं और छोटे किसान लेवी के फन्दे में फांसे जाते हैं?

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

उपाध्यक्ष जी, पिछले साल हमने 130 करोड़ रुपये की सबसिडी की व्यवस्था की थी, लेकिन वह बढ़ गई, 151 करोड़ हो गई, और दाम नहीं बढ़ते तो भी वह हमारी सबसिडी की रकम 160 करोड रुपये हो जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि दाम बढ़ाने पड़ेंगे और इस का परिणाम यह होगा कि एक ओर तो हमें किसान को अधिक देना पड़ेगा और दूसरी ओर हमें इशू प्राइस में भी वृद्धि करनी पड सकती है। इसके परिणाम स्वरूप अनाज अधिक मंहगा होगा। हमारे आम आदमी का अधिकांश बजट खाने की चीजों के ऊपर खर्च होता है। अनाज की कीमत बढ़ती है, खाद्य तेल की कीमत बढ़ती है, सरकार स्वयं वनस्पति की कीमत बढ़ा रही है, चीनी की कीमत में वृद्धि की गई है, तो फिर आम आदमी के जीवन को अधिक कष्टमय होने से नही रोका जा सकता।

मेरा निवेदन है कि हमें एक राष्ट्रीय खाद्य नीति का निर्धारण करना चाहिए। मैं इस बात को स्वीकार करता हू कि आज हम जिस परिस्थिति में है उस में खाद्यान्न दलगत राजनीति का विषय नही रहा सकता क्यों कि अगर हम फैसला भी कर ले कि हमें विदेशों से अनाज मगाना है तो विदेशों मे अनाज उपलब्ध नही है। जिस कीमत पर उपलब्ध है वह कीमत हम दे सकेंगे यह भी सदेहात्मक है। लेकिन नीति के निर्धारण में नारेबाजी से प्रभावित नही होना चाहिए। फिर प्रश्न आता है कि क्या हम व्यवहारिक नीति अपनायेंगे या सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ऐसे कदम उठायेंगे जो आगे जा कर विफल हो जायेंगे और हमारी समस्या को अधिक गम्भीर कर देंगे।

उपाध्यक्ष, महोदय हम अनाज के राजकीय व्यापार के विरुद्ध थे। हम समझते थे कि वह व्यवहारिक नही है। अन्ततोगत्वा सरकार को भी उसी दृष्टिकोण पर आना पड़ा। चावल के राजकीय व्यापार को छोड़ना पड़ा। अब मोटे अनाज पर आवागमन पर लगे हुए प्रतिबन्ध हटा दिए गए हैं; मेरा निवेदन है कि आज की स्थिति में नियत्रण कृत्रिम अभाव पैदा करते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं, चोरी छिपे सामान ले जाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते

उपाध्यक्ष महोदय, कभी कभी मुझे लगता है कि आज देश को रफी अहमद किदवई की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री कोई वित्तीय जादूगर की तलाश में हैं, इकोनामिक विजार्ड ढूढ़ रही हैं। प्रश्न व्यक्ति का नहीं है, प्रश्न नीतियों का है।

नियत्रण तब तक सफल नही हो सकते जब तक नियत्रणो के परिणामस्वरूप बाजार मे कृत्रिम अभाव पदा हाता है तो उसे पूरा करने के लिये सरकार के पास पर्याप्त भडार न हो। आज स्थिति यह है कि नियत्रण लगाते ही सामान बाजार से गायब हो जाता है, भाव बढ़ जाते हैं। अगर सरकार इतना भडार रखे कि लोगो की आवश्यकता पूरी कर सके तब तो नियत्रणो के सफल होने की सम्भावना है, अन्यथा नियत्रण बीमारी का ऐसा इलाज है जो बीमारी से भी अधिक खराब है। मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर व्यावहारिकता की दृष्टि से विचार होना चाहिये। क्रान्तिकारी यथार्थवाद, रेडिकल रीयलिज्म, केवल यथार्थवाद नही, क्रान्तिकारी यथार्थवाद हमारा मार्गदर्शक होना चाहिये। कोरा यथार्थवाद यथास्थिति को बनाये रखने का प्रयत्न हो सकता है। लेकिन अयथार्थवाद क्रान्ति जीवन को परिवर्तित करने की सामर्थ्य नही रखती है। वह आकर्षक नारे के रूप में भले ही हमारा मन मोह सकती है। आवश्यकता है क्रान्तिकारी यथार्थवाद की और यथार्थवादी क्रान्तिकारिता की। आर्थिक क्षेत्र में अगर हम इसे अपना मार्ग निर्देशक बना सके तो हम परिवर्तन के साथ प्रगति कर सकते है। परिवर्तन अवश्यम्भावी है। विषमता घटनी चाहिये। लेकिन आज स्थिति यह है कि जीवन जसे जड़ हो गया है और परिवर्तन की आकांक्षा हिंसा का रूप ले कर गुजरात की सड़कों पर तांडव कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय मैंने देखा जामा मस्जिद के इलाके में होटलों के सामने बड़ी संख्या में रोज शाम को भूखे इकट्ठे हो जाते हैं। हर होटल के समने भूखों की भीड़ लगी हुई है। वह मांगते नहीं है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। मगर एक कामना जरूर करते हैं कि होटल में से कोई खाने वाला निकल कर उन के लिये भी थोड़े से भोजन का प्रबन्ध कर देगा। मैं चाहूंगा प्रधान मन्त्री महोदया उस दृश्य को जा कर देखें। मैं कल गया था इसीलिये कह रहा हू। एक ओर यह दृश्य है और दूसरी ओर यह दृश्य है कि बड़े-बड़े होटलों में, फाइव स्टार होटलो में बैठने के लिये जगह नही मिलेगी, ऐसी भी सम्भावना है। यह खाई बढ़ रही है। यह बढ़ती हुई खाई हमारे सारे लोकतान्त्रिक ढांचे के लिये सकट पैदा कर रही है। लेकिन सारी शक्ति सरकार के हाथ में केन्द्रित करने की अर्थ-व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। हम लोकतान्त्रिक ढांचे में तानाशाही फैसले नही कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्तीय अनु-शासन की क्या स्थिति है? क्या वित्त मन्त्री राज्यो को इस बात के लिये विवश कर सकते हैं कि रिजर्व बैंक से ओवर ड्रा करने के सम्बन्ध में जो नियम बनाये हैं उन का पूरा पालन किया जायेगा? मुझे डर है यह पालन नही होगा।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : कुछ हद तक हो रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कुछ हद तक मगर वह पर्याप्त नही है। आप राज्यो के बजट देखिये? घाटे के बजट आ रहे है। हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर का बजट आया। वह समझते हैं कि केन्द्र के पास पूंजी है और हम अगर साधन न भी जुटायें, हम अपने खर्चों में कमी न करें, तो भी केन्द्र हमारी सहायता के लिये आयेगा। उत्तर प्रदेश में चुनावों के अवसर पर नव निर्माण के कार्यों की जो बाढ़ आयी उसे देखते हुए राज्यों से वित्तीय अनु-शासन की आशा नहीं की जा सकती। अब चुनाव के लिये आप राज्य को 550 करोड़ रु० की नई योजनायें शुरू करने के लिये छूट दे सकते है तो चुनाव गुजरात म भी आ रहे हैं, फिर वहां आप को अधिक रुपये खर्च करने पड़ेगें। मेरा निवेदन है कि राज्यों को वित्तीय अनुशासन में लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। राज्यो को यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि अगर वह अपने साधनों से अपने विकास केलिए मार्ग प्रशस्ट नही करेंगे तो उन के प्लान आउटले में कमी होगी।

वित्त कमीशन ने इस बार राज्यों को अच्छी सहायता दी है, और जो राज्यों को साधन प्राप्त है, जो वित्त प्राप्त है, उस के चलते उन्हें अपने विकास के लिये प्रयत्न करने में अत्यधिक कठिनाई नही होनी चाहिये। लेकिन वित्तीय अनुशासन राज्यों में नही है, वह हमें लाना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: वित्त मन्त्री महोदय ने यह प्रयत्न किया है कि अपने बजट को पांचवीं योजना के पहले साल में समन्वित कर के देखें और दोनो में तालमेल बठाये: लेकिन मुझे लगता है कि तालमेल बठा नही है। योजना का केवल हार्ड कोर" रह गया है और बाकी की सारी योजना की छुट्टी सी हो गई लगती है।

यहां तक कि कृषि के अन्दर पिछले वर्ष की तुलना में एक करोड़ रुपया कम दिया गया है। जल तथा विद्युत में 39 करोड़ की कमी है। सोशल और कम्युनिटी सर्विसिज में 90 करोड़ कम है। ड्राउट प्रोन एरियाज प्रोग्राम में केन्द्र ने बहुत कम राशि रखी है। राज्यों कितना इस मद में धन मिलेगा। इसके बारे में मुझे सन्देह है: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की जिन योजनाओं का बड़े ढोल ढमाके के साथ श्री गणेश किया गया था वे आज अस्तव्यस्त पड़ी हैं: उत्तर प्रदेश में प्रधान मन्त्री द्वारा परिचा-लित परियोजनाओं के खाली साइन बोर्ड रह जायेंगे, उनके अन्तर्गत निर्माण के काम नही होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने मिनिमम नीडस प्रोग्राम के लिये भी जो पहले व्यवस्था की थी अब उसको भी समाप्त कर दिया गया है। एक ओर सामाजिक और सामुदायिक विकास सेवाओं के लिए धनराशि कम हो रही है और

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

दूसरी ओर सेंट्रल रिजर्व पुलिस पर धनराशि बढ़ती जा रही है। 1966-67 में वह 7 करोड़ थी, 1970-71 में वह 17 करोड़ हो गई और 1971-72 में 23 करोड़ और अब 40 करोड़ से ज्यादा हो गई है।

मैं अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाना चाहता हूं। वित्त मन्त्री महोदय जो कर प्रस्ताव लाए है उन में एक प्रस्ताव सर्वथा आपत्तिजनक है और वह है पोस्ट कार्ड की कीमत मे पचास प्रतिशत की वृद्धि का। मेरा निवेदन है कि यह प्रस्ताव उन्हें वापिस ले लेना चाहिये। डाक और तार को रिपोर्ट के अनुसार उसका मुनाफा बढ़ा है, टेलीफोन अधिक आमदनी दे रहे हैं। पोस्ट कार्ड को दाम अलग करके नहीं देखा जा सकता। ताज्जुब की बात हैं कि पोस्ट कार्ड के दाम एक दम पचास फीसदी बढ़ गए हैं लेकिन लिफाफे के पचास प्रतिशत नहीं बढे हैं। इस ढंग से बोझा डालना कि सब पर समान रूप से न पड़े वित्तमंत्री का इरादा हो सकता है मैं नहीं समझता पोस्ट कार्ड के बारे में पुनर्विचार होना चाहिये।

दूसरी बात यह हैं कि आयकर में जो छूट दी गई है वह बहुत देर दो गई हैं और बहुत थोड़ी दी गई है। इसको 7500 रुपये होना चाहिए था। वित्त मंत्री महोदय ने कहा हैं कि थोड़ी सी, माइनर सी कमी हैं छः हजार तक किया हैं। अगर आप मूल्यों का हिसाब लगाएं तो यह छूट अब दस हजार रुपया होनी चाहिए थी। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय इस पर भी विचार करें।

आयकर में जो कमी की गई है उसमें हर एक स्तर पर समान रूप से छूट नहीं मिली है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जिसकी आमदनी दस हजार है उसे 22 रुपये की छूट मिली है, लेकिन जिस की आमदनी सत्तर हजार है उसको चार हजार की छूट मिली है। लेकिन जिस की आमदनी दो लाख रुपया है उसे बाईस हजार रुपये की छूट मिली है। अधिक आमदनी वाले की छूट ग्यारह फीसदी है, बीच की आमदनी वाले की साढ़े पांच फीसदी और छोटी आमदनी वाले की बाईस फीसदी। मैं समझता हूं छोटी आमदनी वाले को अधिक छूट मिले इस में किसी का विरोध नहीं हो सकता है। लेकिन ऊंची आमदनी और बीच की आमदनी वाले के बीच में जो अन्तर है उसको आप देखें। बीच वाली आमदनी वाले को कम छूट मिली है। यह ठीक नहीं है। इस दृष्टि से भी इसको देखने की जरूरत है।

चौथी बात यह है कि सरकार निश्चय करे कि एक वर्ष में पांच प्रतिशत से ज्यादा मनी सप्लाई नही बढ़ने दी जायगी। आर्थिक विशेषज्ञों ने भी इस तरह की सिफारिश की है। वित्त मन्त्री अगर इस सीमा के बाहर जाना चाहते हैं तो उन्हें पार्लिमेंट के सामने आना चाहिये और उसकी स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिये। अधाधुंध नोटों की छपाई हमारी अर्थव्यवस्था को विनाश के कगार तक ले जाएगी, इस में कोई सन्देह नहीं है।

आखिरी बात यह है कि सरकार अपने खर्च में कमी करे: इस बार वित्त मन्त्री ने इसकी चर्चा ही नहीं की है। अगर देश संकट में है तो उस संकट की ही अनुभूति शासन को और समाज को है, यह हर एक वर्ग को दिखाई देना चाहिये। प्रधान मन्त्री अपील कर रही है कि युद्ध स्तर पर हमें समस्याओं का समाधान करना है। जनता से अधिक कष्टमय जीवन बिताने की अपीलें की जा रही हैं। मैं समझता हूं कि सरकार खर्चे में और अनुत्पादक व्यय में कमी करके सादगी का वातावरण बना कर अगर हम चलें तो इस आर्थिक संकट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सरकार को किसी भी वाद-विवाद से ऊपर उठना पड़ेगा।

श्री नाथू राम मिर्धा (नागौर): सब से पहले मैं आप की मार्फत पार्ट 1 के पैरा 27 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहां पर इन्होंने लिखा है:

"While every effort has been made to provide resources to stimulate industrial production, the requirements of the agricultural sector have not been ignored.

इस वाक्य को मैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं देश के लिए। आर्थिक समीक्षा तथा बजट भाषण का जो टोन है इस वाक्य को लिख कर और इसी वाक्य के वह सब समाप्त हो जाता है और इस वाक्य के मुताबिक बजट को बनाने में देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। जो आज परिस्थितियां है और जो समस्याएं आज देश के सामने हैं, जिन कठिनाइयों में से हो कर देश गुजर रहा है, हमारे यहां सब चीजों की कमी है, पैसा और मुद्रा ज्यादा फैली है और इस सब के बीच में अगर कहीं आशा की किरण वित्त मंत्री जी ने देखी तो देश के कृषि उत्पादन में देखी। कृषि का उत्पादन पिछले दो साल में खराब रहा है। इस साल कुछ सुधार है और आगे भी कुछ सुधार की आशा दिखाई देती है। एक आशा की जो टिमटिमाती किरण कहीं नजर आ रही थी इन सब मुसीबतों में से निकलने की तो वह कृषि उत्पादन में ही नजर आ रही थी। लेकिन उसके साथ क्या सलूक हुआ है, कृषि उत्पादकों के साथ क्या सलूक हुआ है। आप पांचवी योजना को लें। आप 53 हजार करोड़ रुपये की योजना बना रहे हैं। चौथी योजना के मुकाबले में यह दुगनी से भी अधिक बड़ी है। पांचवी योजना का यह पहला वर्ष है। पांचवी योजना की शुरूआत ही इस बजट से हो रही है। इस वर्ष में योजना के धन में कुछ वृद्धि होती, काम में वृद्धि होती, काम करने के तरीकों में फर्क नजर आता तो मैं समझता हूं कि हम को संतोष होता। लेकिन कोई फर्क नहीं है। मैं वाजपेयी जी की बात से सहमत हूं। कृषि और कृषि से सम्बन्धित आप सारे प्रोग्रामों को देखें। उनके लिए आपने 216 करोड़ की व्यवस्था की है। 246 करोड़ आपने इसलिए कहा है कि चालीस करोड़ गांवों के विद्युतीकरण के लिए राज्य सरकारों को और देने की बात कही है। इस तरह से कुल मिला कर 246 करोड़ का प्राविजन इन में किया गया है। आप पांचवी योजना पर दुगूने से ज्यादा खर्च करना चाहते हैं। कृषि में सारे देश की भलाई देखना चाहते हैं। कृषि उत्पादन के जरिये औद्योगिकरण का आगे कुछ हल निकालना चाहते हैं। लेकिन जब जड़ में ही कीड़ा लगा हो और वह दृष्टिकोण अपनाया गया हो तो जो आप चाहते है उसकी पूर्ति कैसे हो सकती है। यह जो वाक्य है और जो आशा की किरण दिखाई देती थी उस तक यह वाक्य हम को नहीं पहुंचा सकता है। देश को, पार्लियामेंट को अपने तौर तरीकों को बदलना होगा। खेती से जुड़ा हुआ पशु धन है और उसका विकास है। खेती के उत्पादन से ही समस्त औद्योगीकरण का रा मेटेरीयल उपलब्ध होता है। इस वास्ते सबसे पहली प्रायोरिटी उसको आपको देनी चाहिए थी। अगर जरूरत हुई तो आपको सब प्रोग्रामों को छोड़ना होगा अगर हमारे पास धन की कमी है और रिसोर्सिस सीमित है। औद्योगीकरण के आंकड़े आपने बजट में दिए हैं। खास तौर से तेल और कोयले के उत्पादन के लिए जहां पहले 24 करोड़ था वहां अब 97 करोड़ रखा है। बिजली के वास्ते कुछ ज्यादा रखा है, खाद के लिए कुछ ज्यादा पैसा आपने पहले के मुकाबले में प्रोवाइड किया है इसके उत्पादन के लिए ज्यादा प्रोवाइड किया है। पर पैसे का सवाल नहीं है। चौथी योजना के पिछले तीन चार सालो के आंकड़े आप देखें। बिजली के वास्ते पैसेकी कमी नहीं थी लेकिन फिर भी जो लक्ष्य आपने रखे थे उनको आप पूरा नहीं कर पाए। उसके क्या कारण हैं उनको अब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं।

खाद उत्पादन के लिए पहले भी पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी खाद के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाई। इस साल भी सरकार ने इस क्षेत्र के लिए ज्यादा रुपया प्रोवाइड करते हुए कहा है कि यह कृषि और औद्योगीकरण का बेस है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार यह फ़िलासफ़ी और यह थ्योरी बहुत योजनाओं में मानती चली आ रही है, और यह कारगार साबित नहीं हुई है। पांचवी पंच वर्षीय योजना में कृषि विकास का लक्ष्य 4.7 रखा गया है, जब कि सारे विकास का लक्ष्य 5.7 रखा गया है—कृषि विकास के

[श्री नाथू राम मिर्धा]

लक्ष्य को कम रखा गया है, और पहले साल के लिए उस के लिए धनराशि रखी गई उस है, में इस का कोई रिफलेकशन नहीं है। फिरभी हम लोग कृषि में अपनी सारी प्राबलम्ज के लिए आशा की किरण देखते है।

यह कहा जा सकता है कि अगर केवल कृषि का उत्पादन होगा, और दूसरी तरफ़ ध्यान नही दिया जाएगा, तो रा मैटीरियल का क्या होगा। में कहना चाहता हू कि आज दुनिया में कृषि की चीजो की इतनी मांग है कि अगर हमारे पास उन की प्रासेस करके बेचने की व्यवस्था न हो, तब हम उन को रा फार्म में भी बेच कर, एक्सपोर्ट कर के, विदेशी मुद्रा कमा सकते है। खेती से निकलने वाली चीजें हमारी देश की जनता के लिए बुनियादी चीजे है। इस बारे मे सरकार का अपना रूख बदलना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने इस बात पर अपनी चिन्ता प्रकट की है कि हमारे सब प्रोग्राम्ज के इम्प्लीमेंटशन मे कमी रहती है और उस तरफ ध्यान दिया जाएगा। लेकिन मंत्रालयों मे ताल मेल स्थापित करने और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कर के इन योजनाओं के धन को सही ढग से खर्च करने के बारे में कोई नया सोचने का तारिका मुझे इस बजट मे नजर नही आता है।

मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हू कि अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें किसान की मुसीबतों और समस्याओं को समझना होगा। आज सारी दूनिया में एनर्जी क्राइसिस है, तेल की कमी है। कोयला सीधे ही किसान के खेत में काम नहीं आ सकता है। किसान ने जो मशीनीकरण किया है, जो थोड़े बहुत ट्रैक्टर है, उन को चलाने के लिए उसको डीजल आयल तीन गुना कीमत पर मिलता है। जो कुछ खाद हमारे देश मे बनती है, या इम्पोर्ट की जाती है, वह भी दुगने दामों से कम पर किसान के हाथ में नहीं पहुचती है। किसान को खाद, तेल और एनर्जी नही मिल "ाती है। इसी तरह अच्छे बीजों के वितरण का भी कोई तरीका नहीं है। जब सरकार किसानों को बीज, खाद और तेल नहीं दे सकती है, तो फिर कृषि का उत्पादन कैसे बढ़ेगा? अगर कृषि-उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तो हमें खाने के लिए चीजें नहीं मिलेंगी, काटन से जो कपडा बनता है, वह नहीं मिलेगा शक्कर नही मिलेगी और इसी तरह पशुधन के साथ जुड़ी हुई चीजे भी नही मिलेंगी। अगर जरूरत की ये सारी चीजें नही मिलेंगी, तो हम औद्योगीकरण से क्या करेंगे?

बिजली के लिए ज्यादा पैसा रखा गया है। लेकिन एलूमिनियम का उत्पादन बिजली के जरिये होता है। अगर अलुमिनियम का उत्पादन ज्यादा न हो, तो बिजली के तार कैसे खींचे जायेंगे?

मंत्रियों को बहुत सतर्क हो कर सब मंत्रालयों के पारस्परिक ताल मेल के लिए कोशिश करनी चाहिए। हम रोज कोयले, ट्रांसपोर्ट और मजदूरों की हड़ताल वगैरह की कहानी सुनते है। हमें इस का कोई रास्ता निकालना होगा। आखिर किसी मंत्री को जिम्मेदार बनना चाहिए। कोई मंत्री तो यह कहे कि में फला काम मे फेल हुआ हूं, इस लिए मुझे अपने पद से हट जाना चाहिए। कही न कहीं जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस सदन में केवल जवाब देने के लिए जवाब देते रहने से काम नही चलेगा। स्थिति बिगड़ चुकी है और वह और बिगड़ेगी।

मैं प्रधान मंत्री जी और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रियों को ज्यादा सतर्क होकर विभिन्न प्रोग्राम्ज के इम्पलीमेंटेशन के लिए स्पेशल व्यवस्था करनी चाहिए और अभी तक जो कमियां रही हैं, उन को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए मजबूती से कार्य करना पड़ेगा और जल्दी आवश्यक परिवर्तन करने होंगे। सिर्फ़ यहीं नहीं, राज्यों के लेवल पर भी इन बातों को सोचना पड़ेगा। जो मैन-पावर योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में लगी हुई हैं, उनके सोचने

श्रौर काम करने के ढग में परिवर्तन करने की जरूरत होगी ।—उपाध्यक्ष महोदय, आप ने घंटी बजा दी है । मेरा निवेदन है कि आप सदस्यों को तीस चालीस मिनट तक दे चुके हैं । अगर मैं कोई असगत बात कहता हू, तो मुझे फौरन रोक सकते हैं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Vajpayee took the time allotted to his party. You had 4 hours and 55 minutes to your party when you started your speech. Because there were many speakers, your whip requested that each speaker might be given ten minutes. As far as I am concerned, I should like to make it clear that if you want to take two hours of your party's time, you may do so; I have no objection.

श्री नाथू राम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय आप पांच सात मिनट रिलेक्स कर सकते हैं । इसमे आप का भी डिसक्रीशन है । अगर मैं कोई इर्रेलिवेंट बात कहता हू, तो आप रोक दीजिए ।

हमारी समस्यायें बहुत गहन हैं और उनको हल करने के लिए बड़े क्लीयर विचार मनसा वाचा कर्मणा बड़े स्ट्रिक्ट ढग से व्यवहार करने, आपस के ताल-मेल, जो धन प्रोवाइड किया गया है, उसको सही तौर पर खर्च करने की क्षमता और जो कमिया रही हैं, उनको दूर करने की जरूरत है ।

श्री साल्वे ने कहा है कि ऊपर के लेवल पर जो टैक्स घटाया है, वह बहुत अच्छा किया है, लेकिन किसान मालदार है, उस को टैक्स नहीं किया गया है । उधर से श्री इन्द्रजीत गुप्त, जो एक अलग ढंग के समाज की कल्पना रखते हैं, हमेशा किसान पर टूट पड़ते हैं । उन्होंने कहा कि किसान बहुत मालदार हैं, सरकार ने उनको टैक्स नहीं किया । उन्होंने यह भी कहा कि राज साहब की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया है । क्या माननीय सदस्य ने उस रिपोर्ट को पढ़ा है ?

उस रिपोर्ट में दो बुनियादी बातें थीं एक तो यह थी कि जो काश्तकार इनकम टैक्स देता है, अगर उसको खेती से कोई आमदनी होती है, तो उस आमदनी को इनकम टैक्स की आमदनी के साथ जोड़ा जायेगा, और उसको उसी स्लैब पर टैक्स किया जायेगा । मैं बताना चाहता हूं कि फ़िनांस मिनिस्ट्री ने इस बात को मान लिया है, इसको लागू कर दिया है और ऐसे लोगों को टैक्स कर दिया है ।

उस रिपोर्ट की दूसरी बात यह थी कि लैंड रेवन्यू नही होना चाहिए, बल्कि हर होल्डिंग पर टैक्स लगाया जाना चाहिए । उन्होंने इसके लिए एक काम्प्लिकेटिड फार्मूला सुझाया और कैलकुलेट कर के बताया कि लैंड रेवन्यू को हटा कर इस टैक्स को लगाने से 200 करोड़ रुपये की ज्यादा आमदनी हो जायेगी ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार की जितनी भी रिपोर्ट्स निकली हैं, उनमे राज कमेटी की रिपोर्ट सब से ज्यादा इमप्रैक्टिकेबल है । क्या ऐसी रिपोर्ट को करोड़ो अनपढ़ किसानो पर लागू किया जा सकता है ? मैं चाहता हूं कि श्री इन्द्रजीत गुप्त को दस गांव सौंप दिये जायें और उनको वहा पर इस सुझाव को लागू करने के लिए कहा जाये और साथ ही उनको यह भी बता दिया जाये कि दो साल के बाद उनको वहां से वोट लेने होंगे । मैं समझता हू कि उसमे वह जरूर हार जायेंगे ।

लेकिन ऐसी बातों को कहना बहुत आसान है । साल्वे साहब उम्र भर करोड़पतियो की वकालत करते रहे हैं और कहते हैं कि किसान को नहीं छेड़ा है । कुछ ऐसे लोग हैं, जिनका यह धर्म बन गया है कि छोटे और बड़े के नाम पर किसानो का डिविजन करो और गांव के जमे-जमाये समाज को तोड़ो । कुछ इधर वाले भी यह करते हैं और उधर वाले भी करते हैं । किसान एक है, वह छोटा हो या बड़ा हो । उसको वाजिब टैक्स किया जाये, लेकिन यह ख्याल रखना चाहिए

[श्री नाथू राम मिर्धा]

कि वह इस देश की जान है। उस को सताया न जाये और उसके साथ ईमानदारी का व्यवहार किया जाये। जो ज्यादा पैदा करता है, उस से टैक्स लिया जाये। लेकिन माननीय सदस्य ने कितने किसानों की हवेलियां देखी हैं? जिनके बारे में कहा जाता है कि वे कुछ नहीं कमाते हैं, उन के यहां तो एयर-कन्डीशनर लगे हुए हैं, और जो किसान रात-दिन काम करता है, उसके पास अपने छोरों को बी० ए० पास करने के लिए भी पैसा नहीं है। आज हमारे देश में कितने करोड़पति किसान हो गये हैं? यह एक बोगस नारा है, जो इस तरफ़ से भी लगाया जाता है और उस तरफ से भी। कुछ लोगों को ऐसे, नारा लगाने में मजा आता है।

मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे नारे न उठाये जायें, यथार्थ को देखा जाये और जिनके पास देने की क्षमता है, उनसे जरूर लिया जाये। हम देने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे पास होगा, तो हम कभी इन्कार नहीं करेंगे—देश और समाज के हित के लिए, वर्तमान और आगे की पीढ़ी की उन्नति के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए, और लोकतन्त्र के द्वारा बढ़ाने के लिए, कभी नहीं रोकेंगे :

पर इरादा बद हो तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। आप का इरादा नहीं है लोकतंत्र से बढ़ाने का। बहुत से लोगों का नहीं है, आप के लिए मैं नहीं कहना चाहता हूं। बहुत से लोगों का नहीं है। उन का इरादा है देश में तोड़ फोड़ करो, मजदूरों को लड़ाओ, ज्यादा तनख्वाहें मांगो और उस के बाद काम कुछ मत करो। ये इरादे हैं। लड़ाना चाहते हैं। कभी रेलवे वर्कर्स को लड़ा दिया, कभी ड्राइवर्स को लड़ा दिया, कभी किसी व लड़ा दिया, कभी किसी को उकसा दिया ये सारे काम हैं इन के और गन्दे इरादे हैं। देश की सही रचना ये इरादे नहीं कर सकते। किसानों से हम कहते हैं कि वे चीजें नहीं मिलतीं, आप किसान के एक क्विंटल गेहूं पैदा करने की कीमत को देख लीजिए। प्राइस कमीशन ने कुछ पहले से आगे बढ़ने की कोशिश की है। मैं आप से कहना चाहता हूं देश और दुनिया की हालत को देखते हुए इस से भी हमें कुछ ज्यादा पैसा किसान को देना पड़ेगा। मैं यह भी आप से कहना चाहता हूं कि किसान को ज्यादा पैसा दे कर ज्यादा से ज्यादा गेहूं लीजिए, मैक्सिमम स्टाक बनाइए। कन्ज़्यूमर्स को और गरीबों को देने के लिए व्यवस्था कीजिए। मैं बहुत ज्यादा सबसिडी के पक्ष में भी नहीं हूं। अगर सबसिडी हम सारी खाने में ही चुका देंगे तो इस देश का विकास और इस की तरक्की कैसे होगी? आज भी मोल ले कर डेढ़ रुपये के भाव लोग खा रहे हैं, 2 रुपये के भाव गेहूं ले कर खा रहे हैं। किसान को सौ रुपया दे कर या 110 रुपए दे कर उस की इश्यू प्राइस 125 कर दीजिए। सबसिडी का बोझा मत लीजिए। यह प्रैक्टिकल साल्यूशन है। सरकार को बोल्ड डेसीशन इस के लिए लेना पड़ेगा। कई लोग सस्ती वाहवाही लेने के लिए भाषण देते हुए कह देते हैं कि पोस्ट कार्ड के दस पैसे से पन्द्रह पैसे क्यों कर दिए, 50 प्रतिशत इन्क्रीज हो गई, जनता मर गई। मैं कहता हूं पोस्टकार्ड लिखने वाले हैं कितने इस देश में और वह कोई नहीं मरते। जो पोस्ट कार्ड लिखेगा वह दस की जगह पन्द्रह पैसे देगा। तार के 8 शब्दों के इतने रुपए कर दिए। कोई नहीं मरेगा। यह सारा टैक्स आप ने बहुत बढ़िया छांट छांट कर के लगाया है। मैं एक एक टैक्स का जो आप ने लगाया है समर्थन करता हूं और आप से कहता हूं आप ने 125 करोड़ का घाटा क्यों छोड़ा? और ज्यादा टैक्स लगाइए, इसी तरह की कैटेगरी छांट छांट कर लगाइए। इस से देश के अंदर कोई आदमी नहीं मरेगा। इस से कोई भूखा नहीं होगा, कोई नंगा नहीं होगा। इसलिए यह जो आप ने घाटा रखा है उस को भी पूरा करिए, फिर सप्लीमेंट्री टैक्स लाइए। हम को देश के विकास के लिए, किसानों के इंजन चालू करने के

लिए, बिजली और लगाने के लिए और चीनी और गन्ना, और कपड़ा पैदा करने के लिए धन बहुत चाहिए। इस लिए आप लगाइए। कुछ बातों में हमारा दिमाग साफ होना चाहिए। हम को बोल्ड फैसले कुछ करने पड़ेंगे। उस के लिए कर्मठता अपनानी पड़ेगी और क्लीयर कट नीति तय करनी पड़ेगी। नये नारों से घबराने की जरूरत नहीं है। नये नारे हम भी उठाएं तो उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जरा और बोल्डनैस अपनाइए और कर्मठता से फैसला करके आगे चलिए। इस देश में जहां किरण दिखती है वही आशा की किरण है। पर आपकी कथनी और करनी में फर्क है। इस लिए थोड़ा मैं ने आप को इशारा किया। और बातें बहुत कहीं जा सकती हैं, लेकिन में इतना ही कह कर समाप्त करता हूं।

श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट का समर्थन करता हूं क्योंकि बजट जो बनता है वह पार्टी की नीति आधार पर बनता है। तो जो हमारी पार्टी की नीति है उस के आधार पर यह बजट बना है। अगर हमारी पार्टी की नीति रशिया की तरह होती तो हमारे चव्हाण साहब ब्रेजनेव की तरह बजट बनाते। तो जो बजट प्रस्तुत हुआ है उस का मैं समर्थन करता हूं। क्योंकि मैं उस पार्टी का हूं।

मैं देख रहा हूं कि विधान ही हमारा ऐसा है क्योंकि आदमी अगर ऊंट पर बैठेगा तो हिलेगा। अगर अच्छी सवारी होगी तो नहीं हिलेगा। हमारा विधान बिलकुल खत्म करने के लायक है। आज क्या किसी गरीब को न्याय मिलता है ? यह सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देनी चाहिए, हाई कोर्ट खत्म कर देनी चाहिए। होना क्या चाहिए ? गांधी जी के स्वप्न का पंचायत राज। गांव पंचायत होनी चाहिए। जिला परिषदें जिले की अदालतों का काम करें। विधान सभा के लोग हाई कोर्ट का काम करें। और चाय पीने वाले पार्लियामेन्ट के मेम्बर सुप्रीम कोर्ट का काम करें। यह खर्चा सारा खत्म हो जाएगा। यह व्यर्थ की फिजूलखर्ची हमारे ऊपर लदी हुई है। और ये वकील जो इतने ज्यादा है देश में यह क्या करते हैं ? उत्तर प्रदेश के एक जिले में चार लाख की आबादी है और साढ़े छः सौ वकील हैं। अब कहिए क्या होगा ? साढ़े चार सौ गांव नहीं हैं। ये वकील जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक काम नहीं होगा। 90 प्रतिशत मामले गांव पचायत को दीजिए। कुछ जिला परिषद को दीजिए और थाने की सारी पुलिस जो है ब्लाक प्रमुख के अधीन हो। जिला परिषद् के अधीन जिला पुलिस हो और मुख्य मंत्रियों के अधीन तो अब भी पुलिस रहती है। लेकिन मुख्य मंत्री क्या हैं ? आजकल हमारे मंत्री क्या करते हैं ? बिलकुल मोहर लगाते हैं और पूरा का पूरा अधिकारियों का राज्य है। एक दारोगा एकएम०पी० से ज्यादा हैसियत रखता है। किसी जमाने में रिपोर्ट होती थी तो मुखिया के दस्तखत होते थे। आज जो चाहे चल जाय, किसी का भी नाम लिखा दे, दारोगा पहुंच जायगा कि आप के खिलाफ यह बात है। विधान नहीं बदला जाता है तो क्या होगा ?

शिक्षा के लिए हरएक नेता बोल देता है कि शिक्षा का परिवर्तन करना है। किस को करना है ? कौन करने आएगा ? क्या खुदा करने आएगा ? क्यों नही करते हो ? शिक्षा के अंदर केवल पढ़ाई नही होनी चाहिए। वहां उद्योग भी सिखाया जाना चाहिए। पुलिस के अंदर भी एक घंटा काम होना चाहिए। पार्लियामेंट के मेम्बर और विधान सभा के मेम्बरों को एक घंटा कृषि का काम करना चाहिए। तब उद्योग बढ़ेगा और काम आगे चलेगा। आज विधान तो हमारा है सड़ियल। हम भ्रष्टाचार की बात कहते हैं। बड़े बड़े लेक्चर इस के ऊपर दिए जाते हैं। पंडित जवाहर लाल ने कहा था कि भ्रष्टाचार करने वाले को फांसी पर चढ़ा

[श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी]

दो। पंडित जवाहर लाल ने कुछ आदमियों के ऊपर मुकदमे चलाए। जिन पर मुकदमे चलाए वह आदमी मर गए हमारे पंडित जी भी मर गए, मुकदमे लेने वाले वकील मर गए लेकिन वह मुकदमे अभी भी पड़े हुए है। यह अदालतें हैं ? इन को खत्म करना पड़ेगा। मैं ने कहा था कि वर्तमान मे एक बेईमान व्यापारी, एक बेईमान अधिकारी और एक बेईमान मिनिस्टर को फांसी दे दी जाय पार्लियामेंट के सामने तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन कभी हम ने किसी भ्रष्ट मिनिस्टर पर मामला नही चलाया है। हम ने उत्तर प्रदेश में कितना कहा कि ये भ्रष्टाचारी मिनिस्टर है। पर एक हमारी नही चली। उन्होंने भ्रष्टाचार की कमाई के बल पर चुनाव लड़े कांग्रेस के खिलाफ। तो बातों से समाजवाद नही आएगा।

मैं अर्थ शास्त्र का ज्ञाता नही हूं। मैं दार्शनिक हूं। आत्मवत सर्व भूतेषु-सारे प्राणी अपने समान है, सारे प्राणियों को खाना चाहिए, सारे प्राणियों को कपड़े चाहिए, सारे प्राणियों को दवाई चाहिए, सारे प्राणियों को न्याय चाहिए। यह भावना होनी चाहिए कि आत्मवत सर्वभूतेषु और मातृवत परदारेषु। हमने शराब बंद करने के लिए धरना दिए है और आज हमारे बड़े बड़े नेता शराब पीते है। उन के ऊपर क्या प्रतिबन्ध है ? अगर कानूनी प्रतिबन्ध नही लगा सकते तो पार्टी से निकाल देना चाहिए। कांग्रेस के अंदर फार्म पर दस्तखत किए जाते हैं कि मैं शराब नही पिऊंगा और यहां कई कांग्रेसियों के मुंह से गन्ध आती है। वे शराब पीते हैं। तो नतीजा क्या होगा ? सिद्धान्त के अनुसार नही चलते है हम लोग। यह सारा खर्चा अगर हम बंद कर दे और गांधी जी की नीतियों पर चले तो सारी समस्या हल हो सकती है। तीन ही नीतियां है। एक तो है रशिया की नीति, दूसरी है अमेरिका की नीति और तीसरी है गांधी जी की नीति, गांधी जी का समाजवाद। लेकिन हम कहीं के नही है। न रशिया के न अमेरिका के और न गांधी जी के हैं क्या हम ? सिर्फ कुर्सियों के चक्कर में हैं। राज्य सभा यतीमखाना है, आप की विधान परिषद यतीमखाना है। किसी समय में विधान बनाने वालों ने विधान लिए बनाया होगा कि कोई बुद्धिमान आदमी या किसी जमात का आदमी रह गया हो तो उसे ले राज्य सभा या विधान परिषद में ले लिया जाय। लेकिन आज ये यतीम खाना बने हुए हैं। लोक सभा में हारा तो राज्य सभा में ले लिया चाहे वह किसी भी पार्टी का आदमी हो आज परेशान है कि कैसे यहां आ कर बैठे। रात दिन चक्कर काटता है। कुर्सी का चक्कर है। इन्दिरा जी के आस पास मक्खी की तरह दौड़ रहे है कि उन को ले लिया जाय। और अटल बिहारी जी के भी दो आदमी आने है, उन के यहां भी पचास चक्कर लग रहे होंगे कि साहब मुझे भेज दीजिए, मुझे भेज दीजिए। असल मे होना यह चाहिये था कि आदमी को मनाया जाता कि आप मिनिस्ट्री मे आ कर काम कीजिए और वह कहता कि मैं नही कर सकता। उस के बजाय आज कुर्सियों के लिए लोग दौड़ रहे है। काम कोई नही करता। हिंसा हो रही है, जगह जगह उपद्रव हो रहे हैं। क्या जिम्मेदारी है गृह मंत्रालय की ? हिन्दु-मुसलमानों के दंगे होते हैं, गरीबों के मकान फूंके जाते है, गृह मंत्री क्यों इस्तीफा नही देते है, क्या उन्होंने उस जगह की रजिस्ट्री करा ली है, वह जगह किसी की बपौती नही है। देश का काम जो उसे सौंपा गया है नहीं कर सके तो उस को अलग हो जाना चाहिये। हमारी पार्टी मे 360 सदस्य है। उनमें काबिल नौजवान बैठे हुए हैं, उनको मौका दे, लेकिन वे नही देते है क्योंकि कुर्सी का चक्कर है।

सवाल यही है कि काम नही करेंगे तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा। हम लोग—देहात वालों को—आधा किलो शक्कर एक परिवार को मिलती है और शहर में एक आदमी को एक किलो मिलती है। अगर एक आदमी के परिवार

में 20 आदमी हैं तो शहर में 20 किलो मिलेगी, लेकिन देहात में एक आदमी के परिवार में चाहे 20 आदमी हों तो भी आधा किलो मिलती है—यह क्या समाजवाद है, मजाक बना रखा है। पूंजीवादी लोग हमारे समाजवाद का मजाक उड़ाते हैं। हम को जनता के पहनने के लिए एक यूनिफार्म बना देनी चाहिए, सब के लिये तय कर देना चाहिये कि मोटा कपड़ा पहनें। जो लोग दिन में तीन बार नई नई पोशाकें बदलते हैं, एक नाटक-सा करते हैं, उन के ऊपर कुछ प्रतिबन्ध होना चाहिये।

हमारे यहां अन्न नहीं है तो आधा पाव अन्न खाकर भी हम जीवित रह सकते हैं यदि एक समान वितरण हो किसी के पास अन्न भरा पड़ा हो और कोई भूखे मरें, ऐसा नहीं होना चाहिये। मेरी बात दार्शनिक बात है। मेरी पार्लियामेन्ट यह पार्लियामेन्ट नहीं है मेरी पार्लियामेन्ट तो मानव-समाज है, जहां मैं कहता हूं—सर्वं खल्विदम्, ब्रह्म—सब कुछ ब्रह्म है, किसी की कोई सम्पत्ति नहीं है, किसी को कोई जाति नहीं है, सब ब्रह्म है। ये बात मैं बाहर कहा करता हूं। मगर मैं यहां न बोलूं तो लोग कहते कि स्वामी जी बोलते नहीं हैं—आज यहां बजट पर बहस हो रही है, न प्रधान मंत्री है और न दूसरे मंत्री हैं। हर तरफ कोई खिचड़ी पक रही है, ऐसे मौके पर तमाम एम० पीज, को, प्रधान मंत्री जी को, सब मंत्रियों को रहना चाहिये, लेकिन सब ने मजाक बना रखा है। इन शब्दों के साथ बजट का इस लिये समर्थन करता हूं क्योंकि मैं कांग्रेस का मेम्बर हूं, जो कांग्रेस वाले कहते हैं, वही कहता हूं।

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash): Mr. Deputy-Speaker, Sir, after completing four Five Year Plans and after spending more than Rs. 50,000 crores, let me ask the Government: What is the achievement in the last 20 or 25 years?

Let me quote the opinion of a leading economist of this country:

"The current economic crisis did not come upon us all of a sudden. Most of its components inflation, social injustice, lopsided industrial expansion, shortages, frequently, in key sectors, lag in agricultural production, food scarcities, balance of payments difficulties, and erratic overall economic growth with per *capita* income and consumption moving in both directions—have been our companions, or familiar periodical visitors since 1955-56, by which time one had fairly settled down to the prevailing economic policy."

This is the opinion of Prof B R. Sheony.

This has been the phenomenon in the last 20 or 25 years. This Government cannot take shelter behind a flood in one year or a drought in another year. This has been continuing in the last two decades or even more than that. Not only that. The rise in prices of all commodities in this country is unique and unprecedented. Nowhere in the world, Nowhere in any country, you can witness such a phenomenal rise in prices.

No doubt, the Finance Minister himself confesses in his Economic Survey and says:

"Taking the year 1973-74 as a whole, the average rise in the wholesale price index stood at 19.2 per cent compared to 7.8 per cent in 1972. This under scores the gravity of the situation. The rise in the wholesale price index had its inevitable impact on consumer price index which also increased by 16.8 per cent in 1973, as against 6.2 per cent registered in the preceding year."

[Shri G. Viswanathan]

This is not the whole truth. The general index of prices was 71.1 in 1955 and it skyrocketed to 248.8 in July, 1973. Now, in the present year, the general index of prices is rising at an annual rate of 45.9 per cent. This is an all time record. This is the achievement of this Government after ruling for 26 years.

After this Budget, they told us that there would be a marginal increase in prices; rather, a five percent increase would be witnessed. But this is not so. According to a survey conducted by the Consumer Council of India, the rise in prices is unrelated to taxation. Prices of things like gone up from 20 to 60 per cent after cigarettes, matches and paste have the announcement of new taxes. Prices of vanaspathi, edible oil, etc., have gone up by 40 to 55 per cent after the announcement of the Budget. Government is supposed to be giving to price control priority over all other objectives. I know from the Government what they have done to control prices, to control the inflation which is causing this price rise.

Let me take up deficit financing which is the favourite of our Finance Minister. It was once advocated by J. M. Keynes in 1934 to deal with unemployment—that was a difficult and different situation. It was an industrially advanced country where Keynes suggested that they should go in for deficit financing. Actually that principle is not at all applicable to our country. Even if Keynes were alive today, he would persuade the Government not to go in for deficit financing. Last year they told us that it would be Rs. 87 crores, but actually it went up to Rs. 650 crores. It is said that it may even be Rs. 800 crores. What do they do? They just go on printing more and more currency notes and put them into circulation. This is not our charge. Even economists, including Dr. V. K. R. V. Rao who was once a Minister, in the Treasury Benches, and four others have pointed out to the Government that between 1970-71 and June, 1973 there has been a phenomenal increase in money supply by 38 per cent whereas the increase in the real output has not been more than five per cent. This is the cause of inflation, and the Government should squarely accept the blame for this inflation. At least now the Finance Minister should take into consideration the opinion of the economists in this country and assure the House that deficit financing will not be more than Rs. 125 crores.

The Government thought that the policy of credit squeeze would have a salutary effect on inflation. No doubt, as far as specilative expenditure is concerned, it had a good effect. But what about industries, particularly the small scale industries? They are put to great hardships and I request the Government that the small scale industries of this country should be exempted from this credit squeeze. Instead of creating more employment, this is going to create more unemployment. I will quote an example. This year they had envisaged an outlay of Rs. 15 crores for the Salem Steel Plant. But it has been cut down to Rs. 3 crores. Because of this, the project is seriously affected and about 7,500 people are going to be thrown out of employment. The people of Tamil Nadu and the Government of Tamil Nadu are seriously concerned about it, are agitated about it. I want the Government to reconsider this and restore the original outlay.

As far as investment and income are concerned, I do not know how it happens that all the economic principles are not at all followed in this country. If we have an accelerated investment, it means that we should have more per capita income.

But what happens in this country? We have been spending more and there is no equivalent increase in the per capita income. Investment during

1960—1971 was 138 per cent larger than the First Plan which makes an annual rate of about 9.2 per cent increase. But, during the same period, the per capita income, the real income, grew only at the rate of 1.4 per cent. I want the Minister to explain why this has happened. Not only that, in per capita income, ours is supposed to be the lowest or one among the lowest in the whole world. In the last two decades ending 1971, the per capita income in Japan multiplied by 10.2 times. It was multiplied by 3 times in Taiwan. It rose by 93 per cent in Thailand. It rose by 74 per cent in Phillipines and 60 per cent in Malaysia. In India during the same period 1960—71 the per capita income of India rose at an annual rate of 1.2 per cent. This is the achievement of this great Government.

15.00 hrs.

Not only that, even within this income, there is a large disparity between the rich and the poor, between the urban and the rural areas. The gap between the rich and the poor is widening day by day—it was pointed out by the previous speakers also. Why this disparity in income between the rich and the poor and between the urban and the rural areas? The people at the top spend an amount for a lunch or a dinner which is almost equivalent or which is enough for a family at the lowest rung for the entire month. You find on one side five-star hotels coming up almost in all cities, multi-storeyed buildings, imported cars and luxury items and grinding poverty on the other side.

The Prime Minister talks of austerity I want her to direct her speech to the affluent minority, not to the people who are living below the poverty lina. This disparity can be easily witnessed when you compare the incomes between the rural and urban areas during the first plan the per capita rural income averaged 27 per cent of the urban incomes and it came down to 24 per cent in the Second Plan and it further came down to 20 per cent in the Third Plan and finally, it slipped down to 18.5 per cent during the last four years of the Fourth Plan. This is how Gandhiji's ideals are being implemented by this Government.

Agriculture as was pointed out by a previous speaker is totally neglected. Those who differ with the Government are sent out of the Planning Commission like Minhas and Gills. The farmer is starved of pesticides and fertiliser is not available. He has to pay a very high price in the black market. Without sufficient fertilisers, pesticides and seeds we cannot become self-sufficient in foodgrains for years to come. We have to depend upon the imported wheat from the United States *via* USSR. What about future production? At least now we have to open our eyes to supply fertilisers pesticides and seeds to the agriculturists.

All of us know what havoc the black money as well as the red money is causing in this country. Both of them are being circulated. Red money comes from outside and black money is produced from inside itself. I think the Government has to unearth the black money and stop red money. Otherwise, the economy of this country will be ruined. Now, our old maximused to be: be lenient while levying the tax but be strict while collecting it. But this Government practises a policy which is *vice versa*. They are very strict while levying the tax but they are very lenient when the question of collection comes. That is why we see so much arrears of income tax and other taxes. I want the Government to take stringent steps to collect all the tax arrears.

We are putting more indirect taxes on the people. This is against all canons of taxation. I want the Finance Ministry to cut down indirect taxes which directly affect the common man or the middle class.

Instead of all the socialist slogan, I want the Government to take up

[Shri G. Viswanathan]

the slogan which was advocated by the late Shri Visweswarayya—produce or perish. Unless we produce, we are not going to solve any problem in this country whether by deficit financing or by borrowing from outside. We have to produce more. There is no short-cut to socialism or *Garibi Hatao*. The Government should constitute a National Economic Council where all the leading economists will be consulted on all problems facing the country and their recommendations should be accepted by the Government. This is the way to solve the economic problems of the country. That is why Prof. Colin Clark has warned the Government that unless we take drastic steps the situation may go out of control.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): Mr. Deputy Speaker, Sir, Mr. Chavan has presented the fourth Budget of his term and it is a very realistic and bold one. He has levied taxes on almost everybody in proportion to his capacity to pay. That is why he needs the congratulation of the nation. Moreover, he has increased the budgetary provisions for Defence by Rs. 300 crores. For that I congratulate him because that is an absolute necessity. For the last four years we have been experiencing various natural calamities like floods, droughts etc. We had the refugee influx problem and then finally we had a war. Because of all these things our economy was put to a great strain.

* *

MR. DEPUTY-SPEAKER: Why do you refer to friendly countries like that? It has nothing to do with the Budget.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Where we had to pay Rs. 200 crores for oil we have to pay Rs. 1,000 crores now.

Sir, the agricultural increase for the last 4 years was only 1.5 per cent whereas the population has increased by 8.5 per cent. This is the greatest disadvantage to our country. The population increase is at the rate of 130 lakhs per year.

Unless and until that population explosion is stopped I don't think there is any possibility of this country going ahead. We are adding huge numbers of population to our present population every year but yet nobody thinks of this important aspect. I do not know whether any appreciable amount has been allotted for family planning. I want to point out that it is only one section of our country which is practising it to the utter exclusion of some other communities. Competition is going on between one community and the other so that they may swell their own numbers. In this competition the sufferers are the Indian nation. In advanced countries the population is doubled in 150 years. In our country it is doubled in 25 years. Where President Nixon had to feed one person. Shrimati Indira Gandhi had to feed 6 persons at the same time. The land-man ratio is reduced considerably in our country. Previously one man had 1½ acres but now it reduced to 3/4 of an acre or even less. This landman ratio is being reduced day by day. How are we to meet the requirements of food, clothing and housing of our people?

That is why I say that the main purpose of this Government should be to concentrate on family planning and make it compulsory on everybody. Those who produce more than two children should not be given any facilities by Government. Unless and until this is done, there is no future for this country.

Regarding exports, unless and until we export this year ten lakhs tonnes of sugar it would be very difficult for us to meet the other requirements of this country. For the first time, after twenty years of our export experience to foreign countries, this year we are going to get Rs. 500 to 600 worth of

**Expunged as ordered by the Chair.

foreign exchange per bag. Unless and until we decide to export ten lakhs of tonnes of sugar to foreign countries, we are not going to meet our other expenditure in this country. We are now going to get very good dividends. I think the Finance Ministry and Commerce Ministry must get together to export ten lakhs tonnes out of what we are going to produce, namely 45 lakhs tonnes of sugar—this is the highest so far produced in this country. And next year, the prospects are going to be very good and so, in return, we should import more fertilisers from the foreign countries so that with these fertilisers, we will be able to improve our crops prospects.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, I would like to refer to Rule 41(xix) under which any discourteous reference to a friendly country is barred even when asking a question. *Pari passu* this will apply also to a speech. Shri Reddy made certain references to Arab countries which have nothing to do with the Budget. These are unwarranted They will not form part of the record.

Shri Balakrishnan.

SHRI K BALAKRISHNAN (Ambalapuzha): Mr. Deputy-Speaker, Sir, when the Finance Minister was presenting his budget. I saw to an interesting Alen's cartoon in a daily which was drawn by one of the Members of Parliament Shri Abu. The cartoon depicted the Finance Minister with a butcher's knife just running after a goose which has laid an egg. The cartoon spoke more of what we can get here than from outside. I was reminded of this when we start rising to speak on general budget. We find certain amounts that are earmarked under various heads that come up primarily in our minds. I do not know whether we can find all the time to discuss all the demands that are mentioned in the budget document. I am sure that even with a little more time at my disposal I may not be able to cover all of them. But, I shall refer to certain salient aspects that have struck me.

We all know—when I say 'we', I include the Members in the Treasury Benches as well—that there is not much meaning in the budget proposals because the actuals that we have in budget have precious little to do with what has been proposed. There has been money going about at large, and if we have been told that there is going to be deficit financing for a particular amount, as the experience of last year shows it is 800 per cent more or eight times more. We may not know exactly what the picture of the present budget is going to be; we can decide it only after we hear what the actuals have been, but the deficit is bound to go up. This disparity between the proposals and the actuals is the real thing for which we have to pinpoint the main reason, namely that there is something fundamentally wrong with our method of working the Government

There is no meaning in people saying that it is a very realistic budget. The one word that has last its meaning in this talk about realistic budget is the word 'realism'. What is realistic about it? If it is to be realistic, it must have a realistic equation with what is happening in the country or what is happening in life or what is happening in the economic processes of our life. If the budget does not equate itself with what is really happening in the economic processes of our life, what is there realistic about this budget? I fail to understand the great realism about it.

The Treasury Benches might have noted one thing. Of course if I had been on the other side of the House, I might also have been forced to begin my speech by saying that I supported the budget. But after the statement that I support the budget by the Members belonging to the party in power, there was not one Member who did not have something very bitter to say about certain of the budget proposals and the way Government were carrying on their activities. I have never heard in my three years here so much

[Shri K. Balakrishnan]

of criticism from Members belonging to the party in power. There is a door and there is at least a window. Just look through it. If you are not very particular about closing all the doors and all the windows, just look through it. When people really want to support the Government and they really want to see the best of what is proposed in the budget, why should it be difficult for them to point out things that are to their relish and why should they have to find over so many things which are not to their relish? It can be said of the Members belonging to the Opposition that they always want to find something wrong with things and they would never like to point out something good about it. But this cannot be said of people belonging to the party in power.

As one of my friends on this side had said nobody can escape the allegation that this is a surrender budget. We know that before the formulation of any budget, there is a lot of lobbying going on, lobbying for this particular measure or that particular measure, for the dropping of these taxes or those levies and so on. All sorts of lobbying go on. Even before the budget was actually presented before us, there was lobbying. In the lobbying there were certain interested that wanted certain taxes to be dropped and certain things to be given up certain valuations of current things to be taken into consideration and so on. When the budget proposals came, we found that there was quite a lot of relief on the front of direct taxes; on the highest plank, of the direct taxes income-tax was lowered down. If in the highest plank these things are dropped and if on the highest plank there is enough opportunity for people to make money and take it, but if at the other levels the real income of the people is shinking, then there is going to be a crisis in economy which I think even this Government would not be able to handle. If for one rupee today a person can purchase a certain quantum of consumer goods or commodities, and if by the end of the running of this budget the same person cannot get the same quantum for two rupees or even three rupees, there is going to be a financial crisis which neither Mrs. Gandhi nor all the Ministers and Members of Parliament put together are going to be able to solve. I am sure if that crisis comes, there is going to be a change-over in the entire polity of this country, a change-over that will lead us to better things than what is obtainable today.

श्री सत्पाल कपूर (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट पर बहस में हमारे कई दोस्तों ने हिस्सा लिया है, लेकिन आज कंट्री में जिस किस्म की प्राबलम्ज को हम फेस कर रहे हैं, उन के बारे में बहुत ठोस ढग से बहस नहीं की गई और उसे के बारे मे उन्होंने राय नहीं दी ।

इस वक्त कंट्री मे अगर कोई प्राबलम्ब है तो वह प्राबलम्ब है क्राइसिस आफ प्राडक्शन—हम किस तरह इस मुल्क के प्राडक्शन को बढ़ाये। यहां जब इधर य उधर से हम कोई बात कहते हैं तो मेन ऐंगल यह नही होता है कि हम ने कौन सी बात कहनी है बल्कि यह होता है कि हम ने सरकार की कौन सी पालिसी को सपोर्ट करना है और कौन सी पालिसी को अपोज करना है या बिना बात के सरकार को सपोर्ट करना है या अपोज करना है ।

आज हमारे यहां एग्रीकल्चर की प्राडक्शन का सवाल है । पिछले साल हम ने अनाज का व्यापार अपने हाथ में लिया । इस साल सरकार पर यह जोर डाला जा रहा है कि वह इस पालिसी को बदल दे । मैं बताना चाहता हूं कि इस पालिसी में कहीं नुक्स नहीं है। जिन लोगों को सरकार ने उस के इम्प्लीमेंटेशन में इनवाल्व किया है, उन की पोलीटिकल विल उन की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी या लोअर लेवल पर करप्शन, ये तीन बड़े कारण हैं जिन की वजह से पिछले साल हम टारगेट पूरे नहीं कर पाए। इस साल एग्रीकल्चर के मामले में हम इतने सीरियस नजर नहीं आते हैं, जितना हमें होना चाहिए ।

मेरी तजवीज यह है कि यह पालिसी कान्टीन्यू करनी चाहिए। जब तक सरकार एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री मान कर नहीं चलेगी, उस वक्त तक इस मुल्क की एग्रीकल्चर की प्राबलम्ज साल्व नहीं होंगी। सरकार कोई प्राइस फिक्स करे। यह सैकंडरी इस्यू है। एग्रीकल्चर में जो इनपुट्स हैं, उन को प्राडक्शन के साथ लिंक अप करना चाहिए। सरकार इनपुट्स की कीमतें बढ़ाती जाये और फिर साल के आखिर में कहे कि हम ने यह प्राइस फिक्स करनी है, तो वह अनरीजनेबल बात हो जाती है। इस लिए हम यह मान कर चलें कि एग्रीकल्चर के इनपुट्स का प्राडक्शन के साथ लिंक अप करना जरूरी है। सरकार उस को आज करें, पांच साला प्लान में करें, जब चाहे करे लेकिन जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा, तब तक वह एग्रीकल्चर प्राबलम्ज को साल्व नहीं कर सकती है।

हमारे मुल्क से कोयलें की कमी है, ट्रांसपोर्ट की कमी है। लेकिन हमारे यहां इतने दरया हैं जिन को हम बांध सकते हैं और हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर प्राप्त कर सकते हैं। इस मुल्क की सब से बड़ी बदकिस्मती यह है कि हम यहां डेवलपमेंटल टेम्पो कायम नहीं कर पा रहे हैं इन्टर-स्टेट डिसप्यूट्स बढ़ रहे हैं और सैंटर उन का तमाशा देख रहा है। वह इस बात का इन्तजार कर रहा है कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश खुद ही पियन डैम के बारे में और (डिस्ट्रीब्यूशन के बारे) फ़ैसला कर लें और हम उस को सैंक्शन दे दें। इसी तरह सैंटर गुजरात और मध्य प्रदेश का तमाशा देख रहा है।

मैं चाहता हूं कि इस सिलसिले में सैंटर को एक बेसिक पालिसी बनानी चाहिए। एक बात साफ़ है कि जितना पैसा बड़े इर्रिगेशन प्राजेक्ट्स पर खर्च होगा वह स्टेट्स के रीसोर्सिज से खर्च होने वाला नहीं है। वह तमाम पैसा सैंट्रल पूल से जायेगा। सिर्फ़ कुछ एन्ट्री होगी कि पंजाब, हरियाणा या गुजरात के सिर इतना पैसा पड़ा। जरूरत इस बात की है कि सैंटर इर्रिगेशन के तमाम बड़े प्राजेक्ट्स को अपने हाथ में ले और खुद उन को बनाये। झगड़ा डिस्ट्रिब्यूशन के टाइम पर होगा और उस वक्त सैंटर उस का फ़ैसला कर सकता है। बड़े इर्रिगेशन प्राजेक्टस के बनाने पर झगड़ा नहीं है, बल्कि उन के बनने के बाद किस को कितना शेयर मिलेगा इस बात पर झगड़ा है।

डा० के० एल० राव कई साल यहां बैठे रहे लेकिन उन्होंने इस प्राबलम को साल्व नहीं किया। मै चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस प्राबलम को सीरियसली टैक अप करे। अगर वह इर्रिगशन और पावर के बड़े प्राजेक्ट्स के डिसप्यूट्स को साल्व नहीं करती हैं, तो यह उम्मीद करना फ़िजूल है कि देश का प्राडक्शन बढ़ेगा।

मुझे अफ़सोस होता है कि सरकार ने पाकिस्तान से 100 करोड़ रुपये ले लिये और कह दिया कि अब पाकिस्तान को पानी नहीं दिया जायेगा। लेकिन तीन साल हो गये, पैसा हम ले चुके और पाकिस्तान को पानी भी जा रहा है। पंजाब के नौजवान को जो सरहद पर लड़ता है और अपना खून बहाता है इस बात का बड़ा दुख है कि इस बारे में फ़ैसला होने के बाद भी पाकिस्तान को इस लिए पानी जाना बन्द नहीं हुआ कि हम पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के आपसी डिसपूट्स को हल नहीं कर पाये। यह बड़ी ग़लत और फ़िजूल किस्म की बात है। मै तजवीज़ करता हूं कि सैंटर सब बड़े इर्रिगशन और पावर के प्राजक्ट्स को अपने हाथ में ले। तभी हम इस मुल्क की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डवलपमेंट की प्राबलम्ज को साल्व कर पायेंगे।

हमारे दफ़तरों में बहुत ज्यादा ओवर-स्टैफ़िंग है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा कानफ़्यूजन है। ब्यूरोक्रेसी है, इसी

[श्री सतपाल कपूर]

भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। मैं मिनिस्ट्री आफ़ फ़ाइनांस के रोल को चेंज करने की तरफ़ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब बजट में यह प्रोवाइड कर दिया गया कि एजूकेशन मिनिस्ट्री या हैल्थ मिनिस्ट्री ने फ़लां आइटम्ज पर इतना एमाउंट खर्च करना है, तो वह फ़ाइल दोबारा मिनिस्ट्री आफ़ फ़िनांस के पास क्यों जाय? जितनी डीले होती हैं उस का बहुत बड़ा कारण यह है कि उस रुपये को खर्च करने के लिए मिनिस्ट्री आफ़ फ़िनांस की दोबारा मन्जूरी लेनी पड़ती है। अगर इस ओवरलैपिंग को जारी रखा जायेगा, और अगर मिनिस्ट्री आफ़ फ़िनांस के पास यह डबल पावर रहेगी तो उस हद तक गवर्नमेंट की एफ़िशेंसी नहीं बढ़ सकेगी। अगर किसी मिनिस्ट्री ने अपनी कोई स लाना स्कीम बना दी और मिनिस्ट्री आफ़ फिनांस ने कान्सालिडेटेड फ़ंड से वह स्कीम मंजूर कर दी, तो उस मिनिस्ट्री की फ़ाइल दोबारा मिनिस्ट्री आफ़ फ़िनांस के पास क्यों जाये? इस लिए मिनिस्ट्री आफ़ फ़िनांस की इस पावर को कर्टेल करने की जरूरत है। गवर्नमेंट आज सारे मुल्क में जिस किस्म की आई० ए० एस० और आई० पी० एस० की क्लास पैदा कर रही है उस का लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े शहरों के हिप्पी टाइप के लड़के हमारे यहां डिपुटी कमिशनर बना कर भेज दिये जाते हैं, जिन को मालूम नहीं है कि एग्रीकल्चर की क्या प्राबलम्ज हैं, देहात की किस तरह तरक्की करनी है। मैं समझता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन सिस्टम में परिवर्तन लाने की जरूरत है। मैं यह भी चहता हूं कि पच्चीस परसेंट सीटें रिजर्व की जायें उन लोग के लिए जो देहात में रहते हैं। हो सकता है कि देहात के पढ़े लिखे नौजवानों को अच्छी तरह कपड़े पहनना न आता हो, उन को इंगलिश अच्छी तरह बोलना न आता हो लेकिन अगर वे नौजवान आई० ए० एस० में आयेंगे.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This you can say when the Demands for Grants in respect of the Home Ministry are taken up.

श्री सतपाल कपूर: ऐसे तो उपाध्यक्ष महोदय, बजट की हर डिमान्ड किसी न किसी मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखती है, तो मैं यह तजवीज करना चाहूंगा कि 25 परसेन्ट सीटें ही देहात से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों के लिये रिजर्व कर देनी चाहिये। वे लोग आ कर बता सकते हैं कि यह प्राबलम कैसे साल्व हो सकती हैं।

इस बजट प्रपोजल में कटिंग टूल इण्डस्ट्री जो स्माल सैक्टर की है, जिस में कि लोग लाख-दो लाख रुपये से काम शुरु करते हैं उन पर आप ने टैक्स लगाया है। मैं तजवीज करूंगा कि इस लेवी को आप विदड्रा कर लें। यह जो आधे हार्स पावर की मोटर पर काम करने वाली सोडावाटर की फैक्टरियां हैं, बड़े दूर की आप को सूझी पता नहीं किस आर्गनाइज्ड सैक्टर की ड्रिंक्स को पापुलर करने के लिये किस डेपुटी सैक्रेटरी के दिमाग में यह बात आई है कि उन पर भी आप ने टैक्स लगा दिया। यह जो लाखों लोगों पर आप ने यह नया टैक्स लगाया है इस को विदड्रा कर लेना चाहिये। मैं समझता हूं कि चव्हाण साहब जब इस प्रपोजल की तह में जायेंगे तो खुद ही इस को विड्रा कर लेंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude. Your Whip has requested that ten minutes should be given to you. I have given you ten minutes. Please conclude.

SHRI SAT PAL KAPUR: I will speak on Monday.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have a responsibility in regard to so many other Members whose names are here. That is why, I am rationing the time. So, please conclude.

SHRI SAT PAL KAPUR: Then, will speak on Monday.

MR. DEPUTY-SPEAKER: you may have decided to speak on Monday. But, I have not decided. What is the use of my sitting here, if you decide yourself, without the permission of the Chair, that you will continue on Monday?

SHRI SAT PAL KAPUR: Sir, kindly give me five minutes

MR. DEPUTY-SPEAKER You conclude now.

श्री सत्पाल कपूर तो कटिंग टूल और सोडावाटर फैक्ट्रियों के बारे में मैंने आप से कहा। इस के बाद इस सारे बजट मे जो सब से ज्यादा अफसोसनाक बात हमें लगती है वह यह है कि हमारी नैशनल इन्कम का 11.3 प्रतिशत अब तक पब्लिक सैक्टर की यूनिट्स पर लगता रहा है यह पहला मौका है जब आप ने इस बजट मे जो पब्लिक सैक्टर पर पैसा खर्च होना है उस को 8.3 किया है। यह मै समझ नही पाया कि किस लाजिक मे किया गया, क्या प्रैशर और पुल्ज इसमे काम कर रहे है? पब्लिक सैक्टर यूनिट्स के लिये नैशनल इन्कम का 11 प्रतिशत जहा लगता था उस को 8 परसेन्ट अब आप ने कर दिया।

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now take up Private Members' Business.

15.33 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

THIRTY-SEVENTH REPORT

SHRI AMAR NATH CHAWLA (Delhi Sadar): Sir I beg to move:

"That this House do agree with the Thirty-seventh Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 13th March 1974."

MR. DEPUTY-SPEAKER The question is:

"That this House do agree with the Thirty-seventh Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 13th March, 1974."

The motion was adopted

15.34 hrs

RESOLUTION RE. FREE AND FAIR ELECTIONS—contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now resume discussion on the Resolution on Free and Fair Elections moved by Shri Atal Bihari Vajpayee. Originally, two hours were allotted for this. The House extended the time by one hour. Even then, we have a balance of only twenty-five minutes left. Shri Samar Guha was on his legs on the last occasion. He has already taken twelve minutes. He may continue his speech.

SHRI SAMAR GUHA (Contai): Sir, I request that the time may be extended in view of the experience of UP and Orissa Elections.

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT (Kozhikode): Sir, this is a very important Resolution. Time should be extended.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Time will be automatically extended because the Minister has to reply and the mover of the Resolution has also to reply. The only question is, by how much.

Now it is for you to suggest.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior): Let us see how the debate progresses.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): I suppose the Minister will take 20 minutes and the mover 30 minutes. So, I think one hour and thirty minutes will do.

SHRI SURENDRA MOHANTY (Kendrapara): Let us make it two hours.